प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

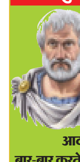

श्रेष्ठ होना कोई कार्य नही बल्कि यह हमारी एक आदत है जिसे हम बार-बार करते है।

अरस्तु

वर्ष-02, अंक - 52 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 01 अक्टूबर 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

मालदीव को भारत ने उपलब्ध कराया डोर्नियर विमान, आतंकवादियों पर रख सकेगा नजर

नई दिल्ली, एजेंसी। मालदीव को एक डोर्नियर विमान भारत ने उपलब्ध कराया है। इससे द्वीप देश अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी में मजबूती ला सकेगा और समुद्री आतंकवादियों पर नजर रख सकेगा। सरकारी सूत्रो की जानकारी अनुसार बताया कि, इस विमान का परिचालन मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (एमडीएनएफ) द्वारा किया जाएगा। डोर्नियर का और इसका परिचालन खर्च भारत द्वारा वहन किया जाएगा। मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 2016 में अपनी भारत यात्रा के दौरान अपने देश के लिए डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान की आवश्यकता जताई थी।

कांग्रेस के दबाव में झुकी उद्धव सरकार, नया कृषि कानून लागू करने का आदेश लिया वापस

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट बैठक के बहिष्कार की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नए कृषि कानून लागू करने का अगस्त महीने में दिया अपना आदेश वापस ले लिया है।

राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की तरफसे महाराष्ट्र में कृषि कानूनों का विरोध कर इसे 'किसान विरोधी' कहने के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार कृषि सुधार कानूनों को लागू करने को लेकर असमंजस में है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में इस कानून को भारी विरोध के बीच पास कराया गया।

पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने ऐलान किया था कि, राज्य सरकार कृषि सुधार कानूनों को राज्य में लागू नहीं करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारों से सोमवार को कहा कि, वे केंद्र सरकार के 'कृषि विरोधी कानूनों' को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहां कानून पारित करने की संभावना पर विचार करें।

27 वर्षों से कुंडली मार के बीईओ कार्यालय में बैठा बाबू जोशी

विभाग में हुई वित्तीय अनियमितताओं का सरगना या प्यादा?

अटकान और जोशी की जोड़ी लगातार कर रही भ्रष्टाचार की बेटिंग, आउट का कोई नियम इन पर लागू नही

माही की गूंज, संजय भटेवरा

आदिवासी विकास विभाग में फर्जी नियुक्ति और वित्तीय अनियमित्ताओं के नित नए-नए खुलासे हो रहै है, ऐसा भी नही की इन फर्जी नियुक्तियो या वित्तीय अनियमित्ता की जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को नही या इनकी कोई शिकायत नही हुई हो, सारी प्रक्रिया होने के बाद भी स्थिति जस की तस रही और किसी भ्रष्ट पर कोई गाज नही गिरी। मतलब साफ है पूरे भ्रष्टाचार के खेल में सिर्फ ये बाबू नही बल्कि इनके रहनुमा अधिकारी भी गले-गले तक शामिल थे इसलिए जाँच के नाम पर आज तक सभी के सभी न केवल बचे हुए है बल्कि उसी जगह आज तक जमे हुए भी हैं ताकि इनकी कार गुजरिया जग जाहिर न हो सकें।

कौंन हैं 1993 से पदस्थ बाबू

वित्तीय अनियमित्ता का पूरा खुलासा गूंज करे इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि, आखिर खण्ड शिक्षा कार्यालय पेटलावद में पदस्थ बाबू (लेखापाल) उपेंद्र जोशी के बारे में जान लेते हैं।

शिकायतकर्ता रमेश धानक द्वारा आरटीआई के अंतर्गत ली गई जानकारी में पता लगा कि बाबू जोशी खंडवा जिले से पदोन्नत होकर वर्ष 1993 में उपायुक्त संभागीय कार्यालय इंदौर के आदेश क्रमांक स्थापना 93/435 इंदौर 18 जनवरी 1993 से खण्ड शिक्षा विकास खण्ड पेटलावद में लेखापाल पद पर पदस्थ हुए, तब से लेकर अब तक महाशय इसी कुर्सी से एसे चिपके हुए है की उनको 27 साल का लंबा अंतराल एक ही कुर्सी पर हो चुका है। सूचना अधिकार में मिली जानकारी में ये भी खुलासा हुआ कि लेखापाल उपेंद्र जोशी न केवल अटकान के परिवार के सदस्य के फर्जी वेतन के भुगतान में ही शामिल नही है वरन् 20 लाख की भारी अनियमिता में भी शामिल हैं। आयुक्त आदिवासी विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./1/डी-2/1930/2016/5352 2 मार्च 2016 द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास झाबुआ ने पत्र क्रमांक/स्था. 01/2016/9565 17 जनवरी 2016 के द्वारा उमेन्द्र कुमार जोशी लेखापाल द्वारा स्वीकृत पद से अधिक मजदूरी में देयक प्रस्तुत कर प्रति वर्ष लगभग 20 लाख रुपए से भी अधिक अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान कर वित्तीय अनियमित्ता के संबंध में जांच शुरु हुई। उक्त मामले उजागर होने पर आदिवासी विकास विभाग में हड़कंप मच गया, लेकिन कहते हैं भ्रष्टो के बचने के सौ रास्ते होते हैं और सेटिंग तगड़ी, अगर पूरे मामले में सही जाँच होती या हो तो केवल बाबू जोशी ही नही विभाग के कई प्राचार्य और अधिकारी भी बेनकाब हो जाते या हो जाए। खेर मामला उजागर होने पर सहायक आयुक्त झाबुआ द्वारा मामले की जांच पूर्ण होंने तक बाबू जोशी को बाउमावि पेटलावद में कार्य हेतु आदेशित किया गया और परिवार की फर्जी नियुक्तियो की जांच में घिरे बाबू रामचंद्र अटकान को चार्ज दे दिया गया, लेकिन सेटिंग के बूते पर बाबू जोशी उक्त आदेश को संभागीय उपायुक्त से निरस्त करवाकर संभागीय उपायुक्त इंदौर के आदेश क्रमांक/आवी./शिकायत/2017/647/ 16 अक्टुबर 2017 से पुनः खंड शिक्षा कार्यालय पेटलावद में पदस्थ हो गए, जिसके बाद 20 लाख की वित्तीय अनियमित्ता की जाँच को बाबू ने इतना प्रभावित किया कि आज तक मामले की न तो सही जाँच न ही तत्कालीन बीईओ और लेखापाल जोशी पर कोई कार्रवाई हो सकी। इतने गंभीर मामले की जांच में घिरे जोशी को अधिकारीयो का ऐसा सहयोग मिला कि उसके बाद भी विभाग में हेरा-फेरी कर साथी मित्र अटकान के रिश्तेदार का वेतन भी नियमो को ताक में रख कर निकाल दिया।

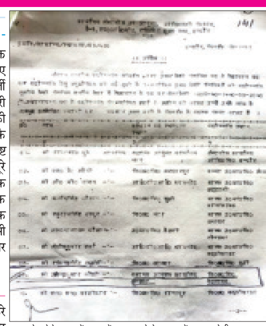

इस आदेश से पेटलावद में 1993 में पदस्थ हुए थे लेखापाल उपेंद्र कुमार जोशी।

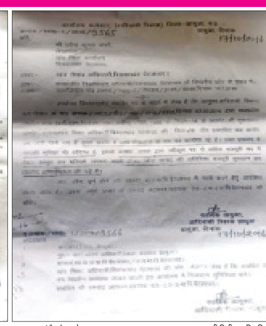

उपायुक्त इंदौर के आदेश पर सहायक आयुक्त झाबुआ द्वारा 20 लाख की वित्तीय अनियमिता के चलते जोशी को बीईओ कार्यालय से हटाने का आदेश।

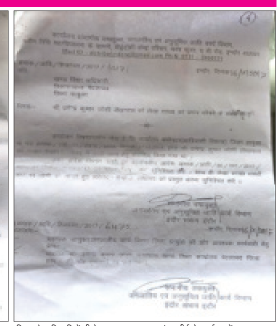

विभाग के अधिकारियों की भेट पूजाकर वापस मूल संस्था बीईओ कार्यालय में पदस्थ हुए उपायुक्त इंदौर का आदेश।

सौतेली मां ने रची बेटे की हत्या की साजिश, पुलिस के खुलासे में सोतेली मां से बेटा करता था छेडखानी

भोपाल, एजेंसी। भोपाल के अवधपुरी इलाके में एक सौतेली मां को उसके ही बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अवधपुरी के वेदवती कालोनी बीडीए अवधपुरी के एक मकान में युवक की हत्या होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों ने बताया कि, तीन अज्ञात लोग घर में घुसकर विजेन्द्र परसौदिया के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस टीम को विजेंद्र के छोटे भाई सौरभ परसौदिया ने बताया कि, तीन अज्ञात लोग अलग-अलग मोटरसाइकिल व स्कूटी से आए थे, वे लोग उनके भाई विजेन्द्र परसौदिया (35) की हत्या कर भाग गए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर किसी भी प्रकार का शोर-शराबा होने से इंकार किया। पूलिस की लोगो से कि गई पुछताछ में किसी भी व्यक्ति द्वारा बाइक व स्कूटी से मृतक के घर तरफ आने-जाने की पुष्टि नहीं की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी किसी प्रकार से बताए गए हुलिये के अनुसार व्यक्तियों के आने-जाने की पुष्टि नहीं हुई। परिजनों से पूछताछ करने पर वह टाल मटोल कर कभी कुछ तो कभी कुछ बताने लगे।

संदेह होने पर थाने लाकर पूछताछ करने पर सौरभ ने बताया कि, विजेन्द्र उसका सौतेला भाई है, जो घर में उसकी मां (विजेन्द्र की सौतेली मां) पर ही बुरी नियत रखता था। विजेन्द्र के अन्य महिलाओं से भी अवैध संबंध थे। आए दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता था। घर में भी मां बाप से लड़ाई झगड़ा करता था, जिससे मां परेशान रहती थी। जब भी पिता कैलाश नारायण बाहर जाते थे तो विजेन्द्र मां से छेड़खानी करता था।

बीते मंगलवार को जब पिता सुबह राजगढ़ चले गए तो विजेन्द्र ने मां से छेड़खानी करने का प्रयास किया, जिससे मां ने अपने प्लान के मुताबिक लोहे की राड से सिर में मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला नीलू और उसके बेटे सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है।

श्रद्धालुओं को दिया न्योता, भव्य महाकुंभ आयोजन का संकेत दे गए प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। हरिद्वार में 2021 में प्रस्तावित महाकुंभ का स्वरूप भव्य और दिव्य होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की शुद्धता और निर्मलता के बहाने यह संकेत दे गए। उन्होंने प्रयागराज के बाद हरिद्वार में गंगा के निर्मलता और अविरलता के सुखद अनुभव को लेकर देश और विदेश के श्रद्धालुओं को एक तरह से हरिद्वार आने का न्योता दिया है।

महाकुंभ के स्वरूप को लेकर लंबे समय से संशय की स्थिति बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अगले साल फरवरी में निर्णय लेने की बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री के कुंभ से जुड़े भाषण को लेकर धर्मनगरी से जुड़ा हर वर्ग बेहद उत्साहित है।

महाकुंभ अपने निर्धारित समय पर होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उसके स्वरूप को लेकर संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी फरवरी में महाकुंभ के स्वरूप को लेकर निर्णय लेने की बात दोहरा रहे हैं। जबकि धर्मनगरी के कारोबारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि, कुंभ भव्य कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने के दौरान व्यापारियों के उत्साह को दोगुना करने का काम किया है।

भारतीय नागरिकता पाने के लिए स्पा मालिक के साथ फरार हुई रशियन युवती

अहमदाबाद, एजेंसी। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए एक रशियन युवती ने वडोदरा के एक परिवार में जहर घोल दिया। मसाज पार्लर चलाने वाले परेश पटेल के साथ पहले उसने प्रेम संबंध बनाए तथा उससे गर्भवती होने के बाद अब उस पर पत्नी से तलाक लेने का दबाव बना रही है। पत्नी ने प्रताड़ना व मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से परेश अपनी रशियन महिला मित्र के साथ फरार है। वडोदरा जेपी रोड पुलिस थाने में जिज्ञाबेन की ओर से दर्ज शिकायत में बताया है कि, उसका पति शहर में कई स्पा व मसाज पार्लर चलाता है।

परेश का एशियन युवती हन्ना चूको के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। वर्ष 2015 में हन्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके पिता के नाम के रूप में परेश का उल्लेख किया गया था। इस बात को लेकर जब परेश व जिज्ञा के बीच विवाद हुआ तो परेश ने बताया कि, हुन्ना भारत का स्थायी वीजा लेना चाहती है, इसलिए उसके नाम का उल्लेख करा दिया। गत दिनों परेश व रशियन युवती ने पत्नी से विवाद होने के बाद उसकी पिटाई की जिसके चलते उसे सिर में 20 टांके भी आए थे। जिज्ञा ने अपनी शिकायत में बताया कि, परेश अपनी प्रेमिका के साथ अकोटा क्लासिक अपार्टमेंट में रहता है तथा वडोदरा के गौत्री रोड व अन्य इलाकों में उसके कई स्पा व मसाज पार्लर हैं। इंदौर का राजन बावा नामक युवक का भी इस केस में नाम आ रहा है। परेश को राजन बावा ही इंदौर से रशियन, थाई व अन्य देशों की लड़कियां स्पा व मसाज पार्लर में भेजता है। पुलिस जब जांच के लिए परेश के फ्लैट पर पहुंची उससे पहले ही परेश अपनी रशियन महिला मित्र के साथ फरार हो गया। पुलिस रशियन युवती के भारत आने व इतने साल से रहने के मामले की भी जांच कर रही है।

बाबरी विध्वंस केसः 28 वर्षो बाद 2 हजार 3 सौ पन्नों में आया फैसला, सभी आरोपी हुए बरी

लखनऊ, एजेंसी। 28 वर्ष पुराने बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 2 हजार 3 सौ पन्नों में इस ऐतिहासिक केस का फैसला लिखा। कोर्ट ने कहा कि, बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत नहीं गिराया गया था। यह अचानक हुई घटना थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस घटना में 49 आरोपी थे। हालांकि 28 साल तक चली सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की मौत हो गई, बाकी बचे 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।

16 सितंबर को सुनवाई पूरी कर लेने के बाद सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अंतिम फैसले के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी। उन्होंने सभी 32 आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा था। हालांकि 6 लोग स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट में पेश नहीं हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े। कोर्ट नहीं पहुंचने वालों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और नृत्य गोपाल दास शामिल थे।

यह 32 लोग थे आरोपीत

बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुधीर कक्कड़, सतीश प्रधान, राम चंद्र खत्री, संतोष दुबे, ओम प्रकाश पांडे, कल्याण सिंह, उमा भारती, राम विलास वेदांती, विनय कटियार, प्रकाश शारना, गांधी यादव, जय भान सिंह, लल्लू सिंह, कमलेश त्रिपाठी, बृजभूषण सिंह, रामजी गुप्ता, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, धर्मदास, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, साध्वी ऋतंभरा, पवन पांडे, विजय बहादुर सिंह, आरएम श्रीवास्तव और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया।

सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की हो गई मौत

बाबरी विध्वंस केस के 17 आरोपियों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है. इनमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सावें, महंत अवैद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे, तत्कालीन एसएसपी डीबी राय, रमेश प्रताप सिंह, महात्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास और विनोद कुमार बंसल शामिल हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा?

फैसला सुनाते वक्त सीबीआई की विशेष अदालत के जज ने कहा कि बाबरी विध्वंस की घटना कोई पूर्व नियोजित नहीं थी। मस्जिद को ढहाए जाने की घटना आकस्मिक थी। कोर्ट ने अखबारों को साक्ष्य नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि, आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा कि, हम सिर्फ तस्वीरों के आधार पर ही किसी को दोषी नहीं बना सकते हैं। इस मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया, उन्होंने बाबरी के ढांचे को बचाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि, 12 बजे विवादित ढांचा के पीछे से पथराव शुरू हुआ। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थीं। कारसेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि, वीडियो कैसेट के सीन भी स्पष्ट नहीं, कैसेट्स को सील नहीं किया गया और फोटोज की निगेटिव नहीं पेश की गई।

भारत ने कहा- पठानकोट और मुंबई पीड़ितों को पाकिस्तान की वजह से नहीं मिला न्याय

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने आरोप लगाया है कि, पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये के कारण मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों के पीड़ितों को अब तक इंसाफनहीं मिल पाया है। आतंकवाद से पीड़ित लोगों के मित्र संगठन से दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की पूर्व सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि, वर्ष 2008 में मुंबई और 2016 में पठानकोट में हुए आतंकी हमलों के पीड़ित अभी भी न्याय की राह देख रहे हैं।

दोनों हमलों के दोषियों को पाकिस्तान के आतंकी समूहों से बढ़ावा मिला और इस संबंध में दिए गए सुबूतों पर पाकिस्तान ने कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। आतंकवाद पीड़ितों के मित्र संगठन की शुरुआत पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने की थी, भारत सहित 24 देश इसमें शामिल हैं। भारतीय राजनयिक ने कहा कि, अपने मंसूबों में सफलता न मिलती देख आतंकी खूनी खेल खेलते हैं और कोरोना महामारी के इस दौर में भी आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है।

भारत 1996 से लगातार अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि के तहत यूएन से आतंकवाद की परिभाषा तय करने की मांग कर रहा है। वैश्विक बिरादरी में अभी तक सहमति न बन पाने की वजह से अभी तक भारत की ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को मुंबई और पठानकोट आतंकी हमले को लेकर कई बार डोजियर दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि 2014 के बाद से पीएम मोदी कई देशों की यात्रा और वैश्विक शिखर सम्मेलनों के दौरान कह चुके हैं कि आतंकवाद सिर्फआतंकवाद होता है।

डीजी सागर सहित तीन आईपीएस होंगे सेवानिवृत्त

राजेन्द्र मिश्रा होंगे पदोन्नत, सायबर सेल की मिल सकती है जिम्मेदारी

भोपाल

पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में पदस्थ डीजी महान भारत सागर के साथ ही सीआईडी में पदस्थ आईजी आईपी कुलश्रेष्ठ तथा अजाक शाखा में पदस्थ डीआईजी आईपी अरजरिया आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एडीजी राजेन्द्र मिश्रा को डीजी वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा। साथ ही उन्हें फिर से सायबर सेल की जिम्मेदारी सौंपी जाना तय है। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के हालिया पारिवारिक घटनाक्रम तथा उनके निलंबन के साथ ही कुछ आईपीएस अफसरों के फेरबदल किए गए हैं। डीजी एसएएफ विजय यादव को शर्मा के स्थान पर अभियोजन शाखा में पदस्थ किया गया है। सायबर सेल में पदस्थ एडीजी मिलिंद कानिस्कर को उनके स्थान पर एसएएफ में पदस्थ किया गया है। यहां पदस्थ डीजी राजेन्द्र कुमार पिछले माह सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके बाद सायबर सेल की जिम्मेदारी कानिस्कर के पास थी। उनके तबादले के बाद तथा डीजी महान भारत सागर की सेवानिवृत्ति से रिक्त पद पर को-

ऑपरेटिव शाखा के एडीजी राजेन्द्र कुमार मिश्रा को डीजी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। उन्हें सायबर सेल में पदस्थ किया जाना तय है। मिश्रा सायबर सेल में लंबे समय तक पदस्थ रहे हैं और वे आईटी एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनके स्थान पर को-ऑपरेटिव फ्रॉड शाखा में किसी एडीजी को पदस्थ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1987 बैच के मिश्रा के अलावा अन्य अधिकारी डीजी वेतनमान में पदोन्नत हो चुके हैं। मिश्रा की पदोन्नति के बाद अब 1988 बैच के अधिकारियों को डीजी वेतनमान में पदोन्नति दी जाएगी। इस बैच के साथ ही 1995 बैच को एडीजी के पद पर पदोन्नत करने के लिए शीघ्र ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होना है।

चार आईजी होंगे पदोन्नत

आईपीएस 1995 बैच के चार अधिकारी ए. साई मनोहर आईजी विजिलेंस (लोकायुक्त), योगेश देशमुख आईजी इंदौर, चंचल शेखर आईजी एसएएफ जबलपुर तथा केपी वेंकटेश्वर राव आईजी बालाघाट को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया जाना है। इनमें हाल ही में इंदौर पदस्थ किए गए देशमुख को इंदौर जोन में यथावत रखा जाना तय है। मनोहर को विजिलेंस शाखा में यथावत रखा जाएगा। वैसे भी विजिलेंस शाखा में एडीजी का पद है। शेखर और राव की पुलिस मुख्यालय वापसी होगी। उन्हें यहां किसी भी शाखा में पदस्थ किया जाएगा। राजेन्द्र मिश्रा की पदोन्नति से को-ऑपरेटिव शाखा में एडीजी का पद रिक्त होगा तो लोकायुक्त संगठन में एडीजी का एक पद रिक्त है। साथ ही एसएएफ जबलपुर और आईजी बालाघाट में दूसरे अधिकारियों को भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक-दो दिन में यह फेरबदल तय है।

डीजीपी जौहरी रहेंगे यथावत

पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी अपने पद पर यथावत बने रहेंगे। उन्हें राज्य सरकार द्वारा सेवावृद्धि दी जाना तय है। मार्च में पुलिस महानिदेशक की कमान संभालने वाले जौहरी का आज कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन उनकी केन्द्र से वापसी के बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें दो साल के लिए डीजीपी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अनुमोदन के साथ ही उन्हें अपने पद पर यथावत रखा जाना तय है। वैसे ही निर्विवाद छवि के जौहरी की बेहतर कार्यशैली और कोरोना काल में कानून व्यवस्था से लेकर सरकार तथा शासन स्तर पर बेहतर समन्वय से तय माना जा रहा है कि उन्हें यथावत रखा जाएगा। हालांकि पिछले कुछ माह से कुछ अधिकारी डीजीपी बनने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुरुषोत्तम शर्मा के घटनाक्रम और उसके बाद फेरबदल से यह तय माना जा रहा है कि जौहरी को अपने पद पर यथावत रखा जाएगा।

मामला नर्मदा के पानी का पूरा उपयोग करने का

आठ परियोजनाओं की राह में रोड़ा बन सकती है पैसे की तंगी

भोपाल

राज्य सरकार ने मप्र की जीवनदायिनी नर्मदा के पानी का उपयोग करने के लिये बड़ी कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। नर्मदा के पानी के पूरे उपयोग के लिए 13544 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत आठ बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरु होगा। नर्मदा घाटी एवं विकास विभाग ने भले ही इस बड़ी कार्ययोजना को तैयार कर लिया है, लेकिन इस परियोजना की राह में अब बजट की कमी रोड़ा बन सकती है।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने भले ही कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन विभाग के पास इसके लिये पर्याप्त राशि की कमी है। इस कारण यह योजना कागजों से निकलकर जमीन में फिलहाल आएगी, इसकी संभावना कम ही है। इस

कार्य योजना के माध्यम से मप्र नर्मदा के 2.84 मिलियन एकड़ फीट पानी के भंडारण की क्षमता विकसित किया जाना है। मिले संकेतों के मुताबिक फिलहाल इस कार्ययोजना पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में अमल होना मुश्किल ही है, लेकिन अगले वर्ष से इसके काम में तेजी आ सकती है। फिलहाल कोरोना के कारण मप्र की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है। ऐसे में इस तरह की बड़ी परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त राशि जुटाना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता इस समय जरूरी कार्यों के लिये राशि का बंदोबस्त करने की है। इस कार्ययोजना के चलते मप्र 2024 तक उसे आवंटित नर्मदा के पानी का पूरा उपयोग कर सकेगा। नर्मदा नदी में बनने वाली परियोजनाओं से मप्र सहित चार राज्यों को फायदा हो रहा है। नर्मदा नदी के पानी के उपयोग के लिये चार राज्यों के बीच सहमति बनी थी। इसमें सबसे अधिक 73 फीसदी पानी पर मप्र का हक निर्धारित किया गया था, वहीं गुजरात के हिस्से में 36 फीसदी, महाराष्ट्र के लिये 2 फीसदी और राजस्थान के लिये एक फीसदी पानी तय किया गया था।

मप्र के लिए 18.25 एमएएफ पानी

संयुक्त कमेटी ने चार राज्यों के बीच नर्मदा के पानी का बंटवारा किया था। नदी पर बनने वाली परियोजनाओं के लिये लागत और पुनर्वास का काम भी उसी अनुपात में तय किया गया था। इनमें से सरदार सरोवर बांध को लेकर ही सबसे अधिक पेंच रहा। इस परियोजना का बड़ा हिस्सा गुजरात में है। इसका फायदा मप्र, गुजरात और महाराष्ट्र को मिल रहा है। इस परियोजना को पूरी ऊंचाई तक भरने के कारण पिछले वर्ष तक विवाद की स्थिति बनी रही। कमेटी ने नर्मदा में कुल 28 मिलियन एकड़ फीट यानी 34537.44 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होना पाया था। इसी हिसाब से चार राज्यों के बीच पानी का बंटवारा किया गया था। मप्र को 18.25 एमएएफ यानी 22511 मिलियन क्यूबिक मीटर का कोटा तय किया गया था। इसी तरह गुजरात के लिये 9 एमएएफ यानी 11101 एमसीएम पानी का कोटा निर्धारित किया गया था। यह दोनों ही राज्य नर्मदा में बनने वाली परियोजनाओं के बड़े भागीदार हैं। इसके अलावा दो अन्य राज्यों को भी कुछ लाभ देकर भागीदार बनाया गया था। इसमें राजस्थान को तकरीबन 50 फीसदी एमएएफ और महाराष्ट्र को तकरीबन 25 फीसदी पानी के उपयोग का अधिकार दिया गया था।

अब तक 15.41 फीसदी एमएएफ पानी का उपयोग

मप्र बीते चार दशक में भी तय किये गये कोटे के हिसाब से पानी का उपयोग नहीं कर सका है। 18.25 फीसदी एमएएफ में से अब तक केवल 15.41 फीसदी एमएएफ पानी का ही उपयोग किया जा सका है। इस कारण भी 2.84 एमएएफ फीसदी पानी कार्योंदी की भेंट चढ़ रहा है। नर्मदा के पानी में भागीदार चार राज्यों ने अब तक 23.64 फीसदी एमएएफ पानी का ही उपयोग किया है। इस तरह अब तक इस परियोजना के तहत 4.36 फीसदी पानी का उपयोग नहीं हो सका है। मप्र नर्मदा से 9839.34 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग सिंचाई के लिये कर रहा है। इसी तरह 307 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग पेयजल पानी के लिये हो रहा है, वहीं 13.04 फीसदी एमसीएम पानी उद्योगों को दिया जा रहा है। मप्र वर्तमान में 15.41 फीसदी एमएएफ पानी का उपयोग कर पा रहा है। मप्र ने वर्ष 2024 तक नर्मदा के पानी का पूरा उपयोग करने का लक्ष्य तय किया गया है।

अपराधियों के बाद अब वारंटियों की बारी

सीआईडी प्रदेश स्तर पर चलाएगी अभियान

भोपाल

प्रदेश में अनलॉक के बाद कुख्यात तथा संपत्ति संबंधी अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ चलाए प्रदेशस्तरीय अभियान के बाद पुलिस अब वारंटियों की धरपकड़ करेगी। उप चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग के निर्देश से पहले सीआईडी मुख्यालय द्वारा यह अभियान शुरु कराया जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस ने जून-जुलाई में प्रत्येक जिले में शीर्ष आपराधिक तत्वों को सूचीबद्ध कर उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही के फलस्वरूप 733 आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। इनमें 133 के खिलाफ एनएसए, 350 जिलाबदर एवं 140 धारा 110 दप्रसं के प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गए थे। जून में चलाए गए विशेष अभियान में 1980 नई हिस्ट्रीशीट फाइल एवं 88 नई गैंग हिस्ट्रीशीट फाइल तैयार की गई। जून में चलाए गए विशेष अभियान में 137 पैरोल पर छूटे अपराधियों की पैरोल निरस्त कराने की कार्यवाही की गई। इसी माह चलाए गए विशेष अभियान में संपत्ति संबंधी अपराधों के 2564 स्थाई वारंटी एवं 375 गिरफ्तारी वारंट तामील कराए गए। जुलाई में 3914 स्थाई वारंट एवं 477 गिरफ्तारी वारंट तामील कराए गए। पिछले चार माहों में 4386 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। पोर्टल के माध्यम से वाहन चैकिंग एवं थानों में रखे वाहनों की सर्चिंग के दौरान जुलाई में 3,45,182 वाहनों को सर्च किया गया, जिसमें 228 अपराधियों से 251 चोरी के वाहन जब्त करने में सफलता प्राप्त की। गुम बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए माह जुलाई में 1,628 बालक-बालिकाओं को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध शिविर लगाकर शिकायतें प्राप्त कर निराकरण कराने के निर्देश दिए गए थे। 275 प्रकरण कायम किए जाकर शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है।

बनाई अपराधियों की हिस्ट्रीशीट

पूरे प्रदेश में चलाई गई मुहिम के तहत लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी, एटीएम में चोरी, मोबाइल लूट जैसे अपराधों में लिप्त 1920 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार कराई गई। धार, झाबुआ, गुना सहित अन्य जिलों में ट्रकों (वाहन कटिंग) में लूटपाट करने वाले संगठित गिरोह की 86 गैंगों की हिस्ट्रीशीट तैयार कराई गई है, ताकि इन पर पुलिस की नजर रहे और वे अपराधों को अंजाम न दे सकें। इसी तरह इन अपराधों में लिप्त फरार 1997 अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है। तीन हजार से ज्यादा स्थायी और गिरफ्तारी वारंटों की तामीली कराई गई है। सीआईडी मुख्यालय के निर्देश पर अब सभी जिलों में स्थायी और गिरफ्तारी वारंटों की तामीली, माफिया, गुंडे-बदमाशों की धरपकड़ के साथ ही वाहन चोरों के खिलाफ संयुक्त मुहिम चलाई गई। इसमें वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की धरपकड़ के साथ ही चोरी गए वाहनों की बड़ी संख्या में बरामदगी की गई। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ से लेकर इनमें लिप्त बड़े तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया गया।

हर जिले में चलेगा अभियान

उप चुनाव की तारीख घोषित होते ही सीआईडी मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधिकारियों को यहां लंबित स्थाई, गिरफ्तारी, जमानती वारंटों की तामीली के निर्देश दिए हैं, साथ ही अपराधी तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदान के दौरान ऐसे तत्व किसी तरह की गड़बड़ी न कर सकें। सभी अधिकारियों से प्रतिदिन की जाने वाली कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजने के साथ ही लंबे समय से फरार वारंटियों के खिलाफ इनाम घोषित करने के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में ऐसे स्थाई, गिरफ्तारी तथा जमानती वारंटों की तामीली की जानकारी पुलिस को चुनाव आयोग को देना होती है। साथ ही आयोग के निर्देश पर लगातार की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी भी देना होती है।

चुनाव सामग्री खरीदने में 19 जिलों में हुआ घोटाला

निर्वाचन अधिकारियों ने किया घोटाला, महालेखाकार ने पकड़ा

भोपाल

चुनावों में अक्सर राजनीतिक दलों के घोटालों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन मध्यप्रदेश में तो चुनाव आयोग ने ही चुनाव उपकरणों में करोड़ों का घोटाला कर डाला है। महालेखाकार की तावातरीन रिपोर्ट ने इस घोटाले को उजागर किया है। महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव कराने के लिये मप्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी सीईओ द्वारा बैलेट यूनिटों को ढंकने वाले वोटिंग कम्पार्टमेंट की खरीदी में 5 करोड़ 77 लाख रुपयों का घोटाला कर अनियमित व्यय किया गया। यह तथ्य महालेखापरीक्षक की ताजा रिपोर्ट में रेखांकित हुआ है। चुनाव के समय मत की गोपनीयता को बनाए रखने के लिये यह वोटिंग कंपार्टमेंट खरीदे गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2017 में सीईओ द्वारा पीवीसी फोम से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट खरीदे गये जबकि उसे भारत चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार, केवल स्टील ग्रे रंग की कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट वाले वोटिंग कम्पार्टमेंट खरीदने थे, क्योंकि ये अपारदर्शी एवं पुनः उपयोग किये जाने योग्य होते हैं।

मप्र में खरीदे गए महंगे वोटिंग कंपार्टमेंट

इन जिलों में गड़बड़ी

महालेखाकार ने 19 जिला निर्वाचन कार्यालयों जबलपुर, सतना, शहडोल, उज्जैन, अनूपपुर, बालाघाट, भोपाल, दमोह, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, कटनी, नीमच, पन्ना, रीवा, रतलाम, शिवपुरी एवं टीकमगढ़ के ऑडिट में उक्त गड़बड़ी पाई। ऑडिट में यह भी पाया गया कि सीईओ ने वोटिंग कम्पार्टमेंट 1644 एवं 1753 रुपये प्रति नग में क्रय किए, जबकि यूपी में इनकी दर 135 से 180 रुपये एवं राजस्थान में 222 रुपये थी। इससे 5 करोड़ 77 लाख रुपयों का अनियमित व्यय हुआ।

सीईओ ऑफिस ने नकारी घोटाले की बात

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कहा कि पीवीसी फोमशीट से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट भी कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट वाले वोटिंग कम्पार्टमेंट जैसे ही हैं। इनकी खरीदी में कोई अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन महालेखाकार ने उनके इस जवाब को सही नहीं माना तथा कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट वाले वोटिंग कम्पार्टमेंट ही खरीदे जाने चाहिये थे। पीवीसी वाले कम्पार्टमेंट महंगे थे।

अब निजी अस्पतालों को टांगना होगी कोविड - 19 के उपचार की दर

भोपाल। प्रदेश के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल (क्लीनिकल स्थापित मेंट) को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके साथ ही मरीज और मरीजों के परिजन को मांगने पर उपचार की निर्धारित दरों को उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित की गई दरों से निर्धारित दरें 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितम्बर और 23 सितम्बर को कोविड- 19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के पारित आदेश के पालन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा सभी नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को उच्च न्यायालय द्वारा कोविड- 19 की रोकथाम संबंधी प्रकरण में 17 एवं 23 सितम्बर को पारित उपचार की निर्धारित दरों के आदेश के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

इंडस्ट्री लगाने मिलेगी प्राइवेट जमीन, शहरों के आसपास जमीन की तलाश शुरू

भोपाल

उद्योगपतियों को सरकार दे रही खास सुविधा

प्रदेश में सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों में जगह की कमी के बीच सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की कवायद में जुट गई है। खास बात यह है कि दूरदराज के क्षेत्रों जाने की बजाए अब शहरी आबादी के के आसपास निजी भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र तैयार करने की योजना है, जिससे निवेशक आकर्षित हो सकें।

इसके लिए मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सक्रिय कर दिया है। भोपाल के आसपास ऐसी निजी भूमि खोजी जा रही है जबकि जबलपुर में बरेला के आसपास के क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। ग्वालियर में फिलहाल इस काम की गति धीमी है। अभी प्रदेश में इंदौर में इस योजना पर काम शुरू हुआ है। उसी तर्ज पर अन्य अंचलों में भी नए इंडस्ट्रियल एरिया की परिकल्पना पर काम किया जा रहा है। इसमें मुख्य भूमिका निजी भू-स्वामियों की है। उनकी सहमति के आधार पर ही उनकी भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन से दोगुनी मुआवजा राशि देकर अधिग्रहण किया जाता है। हालांकि, इसका भुगतान तकरीबन 20 फीसदी नगद किया जाएगा। बाकी भुगतान भू-स्वामियों को उसी इंडस्ट्रियल एरिया में विकसित औद्योगिक या आवासीय भूखंड देकर किए जाने का प्रावधान है। अभी शहर से लगी उतनी जमीन नहीं है, जहां नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके।

मप्र के लिए मांगा 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा से उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री चौहान ने श्री सदानंद गौड़ा से प्रदेश के लिए रबी फसल वर्ष 2020-21 के लिए 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटन की मांग की। चौहान ने श्री गौड़ा से अनुरोध किया कि प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में यूरिया का आवंटन 18 लाख मीट्रिक टन (1.00 लाख मीट्रिक टन रिजर्व) को बढ़ाकर 22 लाख मीट्रिक टन किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रबी वर्ष 2020-21 में प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होने से गेहूं के रकबे में पिछले रबी की तुलना में लगभग 10 लाख हेक्टेयर रकबे वृद्धि की संभावना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में रबी वर्ष 2020-21 के लिए 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होगी।

परिवहन के अफसरों की लापरवाही और अनियमितता से सरकार को लगी 106 करोड़ के राजस्व की चपत

राजस्व कमी की समीक्षा कर नहीं दिया जवाब, कैग ने लगाई फटकार

भोपाल

प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों से मप्र परिवहन विभाग के अफसरों ने कर और दंड की वसूली नहीं की है। जिन वाहनों से कर और जुर्माना की वसूली की है वो भी नियमों के मुताबिक नहीं की है। यानी अफसरों ने कम कर की वसूली की है। इस वजह से परिवहन विभाग को 106 करोड़ 70 लाख रु. का राजस्व नुकसान हुआ है। इस महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब मांगा था और विभाग ने भी राजस्व की कम वसूली बात को स्वीकारते हुए राजस्व कमी की समीक्षा कर जवाब देने की बात कही, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं भेजा गया। महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने नाराजगी जाहिर करते हुए परिवहन विभाग ने स्वीकारण मांगा

लिया है। उल्लेखनीय है कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने साल 2014 से साल 2017-18 के दौरान परिवहन विभाग के लेखों की जांच में यह गड़बड़ी पकड़ी है। कैग ने परिवहन विभाग के साल 2014-15 से साल 2016-17 के लेखों की जांच कराई थी। इस दौरान कुल 5 लाख 67 हजार 274 पंजीकृत वाहनों में से 88 हजार 382 वाहनों के दस्तावेजों की जांच की। इस जांच में सामने आया कि कुल 47 हजार 50 मामलों में 86 करोड़ 12 लाख रु. की कर वसूली में अनियमितता मिली है।

कम वसूली व पेनाल्टी नहीं लेने से हुआ नुकसान

वहीं माल वाहनों के मामले में 1 हजार 709 वाहनों पर कर की कम वसूली और पेनाल्टी नहीं लिए जाने यह सरकार 8 करोड़ 66 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा ठेकेदारी वाहनों, ट्रक शैक्षणिक संस्थाओं में लगी बसों पर कर और जुर्माना की कम वसूली के चलते 47 हजार 273 वाहनों के मामले में सरकार को 66 करोड़ 53 लाख रु. का नुकसान हुआ है। इस तरह कुल 47 हजार 50 वाहनों के मामले में परिवहन विभाग को मैदानी अफसरों की लापरवाही से 84 करोड़ 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साल 2017-18 के दौरान भी 2 हजार 644 वाहनों के मामले में भी कर निर्धारण और अन्य कमियों के चलते 20 करोड़ 58 लाख रु. का नुकसान उठाना पड़ा है। इधर, परिवहन विभाग ने भी मैदानी अमले द्वारा कम कर वसूली की बात को स्वीकारा है और राजस्व कमी की समीक्षा कर जवाब देने का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबे समय से विभाग ने कैग को किसी भी तरीके का जवाब नहीं भेजा।

राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर बीमा को किया अनिवार्य

अब लिफ्ट का उपयोग करने वालों का भी बीमा कराना होगा

भोपाल

प्रदेश में अब कोई भवन स्वामी किसी भवन में लिफ्ट, एस्केलेटर का उपयोग करता है तो फिर उसे इनका तो बीमा कराना ही होगा साथ ही लिफ्ट का उपयोग करने वालों का भी बीमा कराना होगा। राज्य सरकार ने मप्र भूमि विकास नियम -2012 में संशोधन कर दिया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने 12.5 मीटर से अधिक ऊंचे सभी भवनों के लिये लिफ्ट अनिवार्य कर दी है। यहां नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का अब कड़ाई से पालन होगा। किसी भी भवन में स्थापित किए जाने वाले लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक की योजना, डिजाइन, स्थापना, संचालन, रखरखाव और निरीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के भवन सेवाओं के लिए दिए गए प्रावधानों के अनुसार करना होगा। भवन के प्रत्येक स्वामी के लिए यह जरूरी होगा कि वह लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक की स्थापना के लिए भवन अनुज्ञा आवेदन के साथ ही संबंधित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। लिफ्ट की स्थापना का कार्यपूर्णता प्रतिवेदन में भवन स्वामी द्वारा नियमों के तहत पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते समय प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक इकाई का विशिष्ट पंजीकरण क्रमांक प्रदाय किया जाएगा। संशोधित नियमों में प्रावधान किया गया है कि नियम में इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व ऐसे स्थल जिनमें लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापित किए गए हों, प्रत्येक भवन स्वामी को इसके लागू होने की दिनांक से 6 माह के अंदर संबंधित प्राधिकारी को लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक के लिए पांच सौ रुपए प्रति यूनिट की दर से शुल्क के साथ सूचित करना होगा। 6 माह से पहले आवेदन पेश करने पर समुचित कारण सहित पारित आदेश द्वारा 6 माह तक आगे बढ़ाई जा सकेगी, समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक इकाई का विशिष्ट पंजीकरण क्रमांक प्रदाय किया जा सकेगा। यदि भवन स्वामी अपने निजी आवासीय परिसर में लिफ्ट, एस्केलेटर या फिर मूविंग वॉक का उपयोग पहले से कर रहे हैं तो फिर उन्हें इसमें उन्हें छूट रहेगी। राज्य सरकार ने पहली बार नियम को सख्त करते हुए अब आवासीय परिसर में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक लगाने पर उसका बीमा कराने के साथ ही इनका उपयोग करने वालों का भी बीमा कराना अनिवार्य कर दिया है यानी यदि किसी आवासीय परिसर में 50 लोग निवासरत हैं तो यह आवास के स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वह उन सभी का बीमा कराए, जिससे कि किसी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें बीमा का लाभ मिल सके और जोखिम की स्थिति में कुछ राहत मिल सके। यदि किसी आवासीय परिसर में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक सुरक्षित स्थान पर नहीं है तो फिर उसका उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। यदि उपयोग किया तो फिर इसके लिये पूरी तरह भवन का स्वामी उत्तरदायी होगा और किसी दुर्घटना की स्थिति में उसके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकेगी।

बाबरी केस में रामभक्तों के बरी होने पर लवसैनिकों ने जाहीर की खुशी

माही की गूंज, खच्चरटोड़ी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरानें के करीब 28 वर्षो बाद फैसला आया है, इस फैसले का श्री लवसेना लबाना समाज के सभी लवसैनिकों ने स्वागत किया। बता दे कि, लबाना समाज के लवसेनिक प्रभु श्री राम के वंशज मानते है। बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप में 32 लोगो पर केस दर्ज किया था। उन सभी रामभक्तो को इस केस से बरी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना की बाबरी ढांचे को गिराना कोई नियोजित साजिश नही थी न ही इन लोगो नें किसी को इसके लिये उकसाया है। इस केस में लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार सहित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आरोपी बनाए गए थे।

29.71 लाख के तीन सीसी मार्ग का किया विधायक ने भूमिपुजन

माही की गूंज, जोबट। जोबट विधायक कलावती भूरीया ने आजाद नगर(भाभरा) ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवली, डूंगलावानी, काकड़बारी में 29 लाख 71 हजार रुपए की लागत से बनने वाली सड़को का भूमिपूजन कर गेती चला कर कार्य का शुभारंभ किया, जिसमे ग्राम पंचायत देवली में 10 लाख की लागत से सीसी रोड़, ग्राम पंचायत डूंगलावानी में 3 लाख 71 हजार रुपए की लागत सीसी रोड, काकड़बारी में 16 लाख रुपए की लागत से रोड़ के कार्य का भूमिपूजन किया। मौके पर डूंगलावानी सरपंच सुमित्रा बेन, देवली सरपंच सुरजा, काकड़बारी सरपंच तकन, कांग्रेस नेता लईक भाई, भारता भाई, पिंटू मकवाना व ग्रामीण उपस्थित रहे।

स्वच्छता के मामले में झाबुआ नगर पालिका की रेटिंग में निरंतर हो रहा सुधार

गंदगी भारत छोड़ों अभियान में नपा आई प्रथम, इससे पूर्व स्वच्छता के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रह चुकी है

माही की गूंज, झाबुआ।

पिछले एक-दो वर्षो के भीतर नगरपालिका की स्वच्छता, सफाई और गंदगी मुक्त शहर बनाने में मप्र और देश की विशेष टीमों द्वारा सर्वे कर जारी की जाने वाली रेटिंग सूची में निरंतर सुधार हो रहा है। गत वर्ष 2019 में नगरपालिका झाबुआ ने देश और मप्र की सूची में नाम दर्ज करवाया था। इसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत विगत अगस्त माह में जारी सूची मप्र में नगरपालिका झाबुआ को दूसरा स्थान मिला और अब एक और कदम आगे बढ़ते हुए 'गंदगी भारत छोड़ो अभियान' में नपा झाबुआ इंदौर संभाग में प्रथम नंबर पर और मप्र में पांचवें स्थान पर आया है।

शहर को साफऔर सुंदर रखने में एक ओर जहां नगरपालिका परिषद् भरपूर प्रयास कर रहीं है, तो दूसरी ओर सभी शहरवासी भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे है। जिसके कारण ही नगरपालिका झाबुआ की तगमे में निरंतर बढ़ोतरी हो रहीं है। नगरपालिका झाबुआ द्वारा 'गंदगी भारत छोड़ो अभियान' में नंबर-1 स्थान पर आई है। नगरपालिका अध्यक्ष मन्नूबेन डोडियार तथा सीएमओ एलएस डोडिया ने बताया कि नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग भोपाल द्वारा गत 16 से 30 अगस्त तक 'गंदगी भारत छोड़ो अभियान' चलाए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें अलग-अलग थीम पर 5 चरणों में स्वच्छता संबंधी कार्य किए जाने थे। मुख्य रूप से शौचालयों को रखरखाव, कचरों के ढ़ेर हटाए जाना, सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध अभियान चलाना, रिसायकल, रियूज, रिड्यूज तथा रिफ्यूज को नागरिकों के बीच प्रचारित-प्रसारित करना,

कोविड-19 के प्रति जनजागृति, कचरे का पृथकीकरण, सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई आदि सम्मिलित थे। मप्र की समस्त निकायों द्वारा उक्त सभी विषयों पर किए गए कार्यो का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया गया। जिसका परिणाम मंगलवार को सुबह प्राप्त हुआ।

इंदौर संभाग में नंबर वन

जिसमें नगरपालिका झाबुआ को 500 में से 455 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार नपा झाबुआ इंदौर संभाग में नंबर वन पर रहा। साथ ही मप्र में पांचवा स्थान रहा। इस उपलब्धि पर नगरपालिका अध्यक्ष मन्नूबेन डोडियार, उपाध्यक्ष रोशनी डोडियार तथा सीएमओ एलएस डोडिया ने शहर के समस्त पार्षदगणों को बधाई दी। साथ ही विशेष तौर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य कर रहे नपा के स्वास्थ्य अधिकारी यूनूसउद्दीन कुरैशी, स्वच्छता शाखा प्रभारी कमलेश जायसवाल, सहायक स्वच्छता निरीक्षक टोनी मलिया तथा सहायक वर्ग-3 पंकज सोलंकी, आशीष भाबर आदि की दिन-रात सेवाओं की सराहना की है।

2 से 8 अक्टूबर तक चलेगा मद्यपान निषेध सप्ताह

नपा सीएमओ डोडिया ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग मप्र शासन भोपाल के निर्देश पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध तथा तंबाकू गुटका, सिगरेट के सेवन पर रोकथाम हेतु मद्य निषेध सप्ताह संचालित किया जाएगा।

कोरोना वायरस के डर से छाया सन्नाटा

माही की गूंज, कुंदनपुर।

कुंदनपुर में 24 सितम्बर को एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जिसके बाद कुंदनपूर में कोरोना वायरस के डर से दुकानों पर इन दिनों सन्नाटा पसरा है, ग्राहकी ठप हो गई है, बिक्री न होने से दुकानदारों की आमदनी पर ग्रहण लग गया है, जिससे इन दुकानदारों में मायूसी है। पिछले माह से जिस कदर दुकानों पर खरीदारी में भारी गिरावट आई है, उसका असर एसा रहा कि बाजार में दुकानों पर एक भी ग्राहक नहीं दिखे।

शांति समिति की बैठक में बोले एसडीएम एनएल गर्ग, शांति सौहार्द से मनाएं नवरात्रि

माही की गूंज, मेघनगर।

नवरात्रि महोत्सव 17 अक्टूबर से आयोजित होने जा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर इस बार गृह मंत्रालय मध्यप्रदेश सरकार की ओर से नवरात्रि महोत्सव के लिए जारी गाइडलाइन को लेकर कलेक्टर रोहित सिंह ने जिला स्तरीय समीक्षा एवं शांति समिति की बैठक कर चुके हैं। कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देश पर मेघनगर पुलिस थाना प्रांगण में भी शांति समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एलएन गर्ग, तहसीलदार शक्तिसिंह चौहान, प्रशिक्षु डीएसपी विवेक शर्मा, नगर परिषद मेघनगर इंजीनियर गुप्ता, जनपद सी.ओ विरेन्द्रसिंह रावत, पुलिस थाना मेघनगर सब इंस्पेक्टर हिरालाल मालीवाड़ बैठक में उपस्थित थे। एसडीएम गर्ग ने बताया कि, भजन संध्या, चुनरी यात्रा, गरबा महोत्सव आदि कार्यक्रमों का आयोजन इस बार नही हो सकेगा। सारे धार्मिक आयोजन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही करना प्रतिबध रहेगा। गरबा खेलने वाली टीम या अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन करने अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन करने वाली टीम को बुलाने पर पाबंदी रहेगी। गरबे खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

दशहरे को लेकर नगर शांति समिति में किसी भी तरह का निर्णय नही लिया गया। पुलिस प्रशिक्षु डीएसपी विवेक शर्मा ने माता जी की मूर्ति विसर्जन के साथ ही आगामी दिनों में गरबा आयोजन समिति के साथ बैठक करने की भी बात कही।

बैठक में ट्रैफिक अव्यवस्थाओं का मुद्दा छाया रहा

बैठक में पहुंचे समाजसेवी एवं पत्रकारो ने नगर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में प्रशासन को अवगत कराया जिस पर एसडीएम गर्ग ने, व्यापार करने वालों को अपनी दुकान सही क्रम में ओटले के बाहर नहीं लगाना है, दुकान के बाहर लगने वाले टीन शेड को हटाने व नगर में लगने वाले ठेलो को सड़क से 10 फीट पीछे लगाकर नगर परिषद के इंजीनियर को चुने से मार्किंग कर मुनादी कराने के निर्देश दिए। आदेश का पालन ना करने पर चालानी एवं कठोर कार्रवाई करने की बात एसडीएम ने कही। यातायत ट्रैफिक पुलिस जवानों को मुस्तैदी से अपने पॉइंट पर ड्यूटी करने व ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए।

वाहन की टक्कर से गर्भवती महिला सहित एक युवक घायल

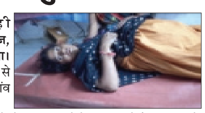

माही की गूंज, रायपुरिया। रायपुरिया से अपने गांव छोट सलूनिया से मोटरसाइकिल से पेटलावद जाने के लिए निकले थे, छोटा सलुनिया फाटे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें दोनों भाई-बहन वहीं पर गिर गए व दोनों घायल हो गए, महिला गर्भवती हैं दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, घायल महिला का नाम तेजू बाई पति कैलाश (23), भाई का नाम दितु पिता रामचंद्र पेटलावद को 108 की मदद से चिकित्सालय भेजा गया। ईएमटी कैलाश अहिरवार, पायलट सुरेन्द्र कुमार ने घटना की जानकारी बताई।

जनजाति विकास मंच की विकासखंड स्तरीय बैठक संपन्न

माही की गूंज, पेटलावद। स्थानीय गायत्री मंदिर पर जनजाति विकास मंच पेटलावद की बैठक संपन्न हुई जिसमें विकासखंड के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक में जनजाति समाज के अस्मिता, अस्तित्व, सामाजिक परंपरा, रीति-रिवाज, हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने पर चर्चा हुई। आगामी 5 अक्टूबर को वीरांगना महारानी दुर्गावती जयंती एवं 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष में जनजाति गौरव दिवस मनाने को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक को जनजाति विकास मंच रतलाम विभाग युवा प्रमुख गौरसिंह कटारा ने संबोधित किया, कटारा ने आगामी कार्यक्रम को लेकर योजना बनाई एवं मंडल स्तर पर महारानी दुर्गावती जयंती मनाने को लेकर योजना बनी। बैठक में शंभूसिंह मालीवाड, शांतिलाल मुनिया, भारत अरड़, हरिसिंह बारिया, दिनेश पारगी, अमृत भाबर, कोमल निनामा, दूल्हा बिलवाल, अमरसिंह गणावा, कैलाश डामर, संतोष भूरिया, संजय भाबर एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आभार संजय मखोड़ ने माना।

नशा मुक्त भारत अभियान का जिले में होगा सघन क्रियान्वयन

माही की गूंज, रतलाम। 29 सितंबर से नशामुक्त भारत अभियान का रतलाम जिले में भी सघन क्रियान्वयन किया जाएगा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के आदि व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको उपचार तथा अन्य मदद की जाएगी, उनके पुनर्वास में सहायता की जाएगी। अभियान के संबंध में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री साबिर अहमद खान, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, उपसंचालक सामाजिक न्याय श्री एस.एस. चौहान, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री के.एन. जोशी, जन अभियान परिषद के जिला संयोजक श्री रत्नेश विजयवर्गीय आदि उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि जिले को नशामुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन के लिए 10 लाख रुपए के बजट का शासन द्वारा प्रावधान किया गया है। अभियान के सफल क्रियान्वयन में अशासकीय संस्थाओं की मदद ली जाएगी। जिला स्तरीय समिति के गठन के पश्चात अब विकासखंड स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। व्यापक रूप से अभियान में जनप्रतिनिधियों एवं जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नशे की लत के शिकार व्यक्तियों की मदद के लिए नशामुक्ति विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएंगी। कलेक्टर श्री डाड ने अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा करते हुए जिला चिकित्सालय में नशामुक्ति केंद्र स्थापना के लिए दो कक्ष आवंटित करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए। नशामुक्ति केंद्र पर नशा पीड़ित रोगी रखे जाएंगे जहां उनका उपचार तथा अन्य सहायता दी जाएगी। एडीजे श्री साबिर अहमद खान ने बताया कि जिले में अभियान के तहत नशा पीड़ित व्यक्तियों को काउंसलिंग तथा

अन्य माध्यम से नशे से मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री केरकेट्टा ने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वॉलिंटियर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे नशा पीड़ित व्यक्तियों को चिन्हित कर सेंटर पर उपचार करा सकें। प्रारंभ में उपसंचालक सामाजिक न्याय श्री एस.एस. चौहान ने नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय कृमी मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

झाबुआ जिले के संपूर्ण विकास खंडों में समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल के द्वारा घर-घर जाकर 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को कृमीनाशन की गोलियां कोविड-19 संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खिलाई जा रही है।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ राहुल गणावा ने बताया कि, संपूर्ण झाबुआ जिले में 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को 28 सितंबर से 7 अक्टूबर के मध्य कार्ययोजना अनुसार स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीयों व कर्मचारियों के आपसी समन्वय से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा एवं जनता से अपील की जाती है कि, वह अपने 1 वर्ष से 19 वर्ष के समस्त बच्चों को कृमीनाशन की गोलियां जरूर खिलाएं जिससे बच्चों का पोषण-स्वास्थ्य एवं एकाग्रता में वृद्धि और कुपोषण, एनीमिया, डायरिया से बचाव संभव हो सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगी के अंतर्गत ग्राम बैंगनबड़ी, मोहनपुरा, बाछीखेड़ा, कसारबड़ी, बोड़ायता, गामडी, भमती, टेमरिया, सारंगी में एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर बच्चों को उम्र वॉइस एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई साथ ही साफ सफाई व कोरोनावायरस से बचने की जानकारी दी गई।

आगे-आगे पाट, पीछे-पीछे सपाट...

नल जल योजना के ठेकेदार द्वारा उखाड़े गए रोडो की रिपेयरिंग के नाम पर हो रही खानापूर्ति

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर में आरो वाटर की पाइप लाईन बिछाने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया जिसके लिए ठेकेदार ने पूरे नगर में लाखो की लागत से बने सीसी ओर डामर रोड खोद दिए जिसे ठेकेदार को रिपेयर करना था लेकिन ठेकेदार ओर नगर परिषद की साठ-गाँठ के चलते खुदे हुए रोड़ो को रिपेयर करने के नाम पर ठेकेदार द्वारा खानापूर्ति मात्र की जा रही है। यहाँ लगभग सभी वार्डो में खुदे पड़े रोड़ को ठेकेदार से रिपेयर करवाने की बजाए पैसा कमाने के उद्देश्य से कुछ दिनों पूर्व ही चुरी बिछा कर नगर परिषद द्वारा भरा गया था, जबकि रोड को पूर्व की स्थिति में नल-जल योजना के अंतर्गत ठेकेदार को करना था, अब उसी चुरी को हटाकर ठेकेदार दिखावे के रिपेयरिंग कार्य कर रहा है जो कि निम्न स्तर का होकर आगे-आगे पाठ और पीछे-पीछे स्पॉट... की स्थिति में कोई जगह पर घटिया निर्माण रिपेयर होने के बाद से उखडने लग गया तो, कई जगहों पर ठेकेदार की लापरवाही के कारण किए हुए कार्यो पर वाहन और जानवर द्वारा बिगाड़ दिए गए।

लाखो के रोड खुदाई की पर इस तरह से भरी गई है जगह-जगह चुरी।

ठेकेदार की घटिया रिपेयरिंग के बाद रोड से जानवरों ओर वाहन के गुजरने से रोड फिर हो रहे खराब

कई लोग हो चुके हैं दुर्घटना का शिकार, मुख्य मार्ग पर उखड़े रोड के टुकड़े जमा कर के कर दिया काम खत्म

पूरे नगर में जगह-जगह रोड खुदे पड़े हैं जिससे कई लोग ओर छोटे वाहन चालक चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। पुर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र भण्डारी भी अपने वाहन से गिर कर घायल हो चुके हैं, बारिश के दौरान इन खुदी हुई लाईन में जल भराव से कीचड़ की स्थिति बनी रही जो आज भी कई वार्डो में बनी हुई है। पेटलावद-रायपुरिया मार्ग के एक हिस्से में बना सीमेंट क्रांकीट का प्लेटफार्म भी ठेकेदार द्वारा जेसीबी मशीनों से उखाड़ दिया और बाद में उसे रिपेयर करने की बजाए उखडे हुए सीमेंट के टुकड़े जस के तस जमा कर कार्य की इतिश्री कर ली। पूरे कार्य मे नगर पालिका की ठेकेदार से बड़ी साठ-गाँठ हैं जिसके चलते परिषद ने कोई कार्रवाई लापरवाह ठेकेदार के विरुद्ध नही की है जिससे नगर की जनता त्रस्त हो कर परेशानी उठाने पर मजबूर है।

एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ केंद्र का किया निरिक्षण, फीवर क्लिनिक को दुरुस्त करने के दिए निर्देश

माही की गूंज, मेघनगर।

एसडीएम एलएन गर्ग ने मेघनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया व फीवर क्लिनिक रूम का भी निरीक्षण किया। श्री गर्ग ने मेघनगर बीएमओ डॉ सेलक्सी वर्मा को निर्देश दिए कि, फीवर क्लिनिक रूम के बाहर सुरक्षा सूचना होर्डिंग दूरस्थ रखने, सर्दी खांसी जुखाम होने वाले लोगो के लिए सुबह 8 से रात्रि 8 तक निरंतर सेवा चालू रखने, जितने भी पेशेंट यदि अपनी कोरोना के स्टिंग कराने आए तो उनका सेम्पल तुरंत लिया जाए। डॉ सेलक्सी वर्मा ने एसडीएम को पूरे हॉस्पिटल का भ्रमण करवाया।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम एलएन गर्ग ने स्वच्छता की दिशा में और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे मरीज को किसी प्रकार की तकलीफ न हो साथ ही पार्किंग व्यवस्था के सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोरोना के संभावित मरीजों व डॉक्टरों को भी मॉनिटरिंग के लिए 'सार्थक' मोबाइल एप के साथ क्वारेंटीन किए गए सभी संभावित मरीज और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इस एप पर रजिस्टर कर उनकी रोज मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ी

पहले कोरोना सैंपल को झाबुआ भेजना पड़ता था व इंदौर से रिपोर्ट आने का इंतजार करना पड़ता था जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते थे। लेकिन अब रैपिड एंटीजन किट को कोराना वायरस की टेस्टिंग शुरू कर दि है जिससे मात्र 30 मिनट में मरीज की रिपोर्ट मिल जाएगी। इस किट को श्माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस की ओर से तैयार किया गया है। जिसमें हाल फिलहाल चार टेस्ट किए हैं जिसमें चारों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वर्तमान में मेघनगर से 1782 सैंपल लिए गए, 80 लोग पॉजिटिव पाए गए वहीं 98 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है जिसमें वर्तमान में 10 केस एक्टिव हैं। अब एंटीजन किट से रिपॉर्ट में तेजी का लाभ निश्चित रूप से मिलने की बात डॉ सेलक्सी वर्मा ने कही।

सोनू डावर होगी पेटलावद की नई एसडीओपी

माही की गूंज, पेटलावद। उपचुनाव की तारीखों के ठीक पहले प्रदेश में हो रहे थोकबंद तबादलो के बीच पेटलावद एसडीओपी बबिता बामनिया का स्थान्तरण उप पुलिस अधीक्षक, अजाक रायसेन में कर दिया गया। वही इंदौर झोन में पदस्थ सुश्री सोनू डाबर को पेटलावद भेजा गया है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बीच पिछले कई दिनों से कई विभागों में जमकर तबादलो की झड़ी लगी हुई है। पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेलबदल हुआ है कई अधिकारियों का एक साथ स्थान्तरण किया गया है, सूची में झाबुआ में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक स्टेला सुलिया जो पेटलावद एसडीओपी भी रह चुकी हैं उन्हें भी होशंगाबाद भेजा गया है। एक-दो दीन में पेटलावद की नवागत एसडीओपी सोनू डावर चार्ज ले सकती हैं।

संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर पीएम मोदी के प्रासंगिक सवाल

पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की प्रासंगिकता और मौजूदा दौर में उसके प्रयासों पर सवाल उठाए हैं। बीते आठ महीनों से दुनिया कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी की गिरफ्त में है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने जानना चाहा है कि इस दौरान यूएन कहां था और उसने क्या सार्थक भूमिका निभाई? उन्होंने यह स्वीकार किया कि कहने को तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसे नकार नहीं सकते कि अनेक युद्ध हुए हैं, गृहयुद्ध भी हुए हैं, कितने ही आतंकी हमलों ने खून की नदियां बहाई। इन युद्धों और हमलों में जो मारे गए, वे भी हमारी तरह इनसान थे। लाखों मासूम बच्चे, जिन्हें दुनिया पर छा जाना था, उन्हें दुनिया छोड़ कर जाना पड़ा। उस समय और आज भी, क्या यूएन के प्रयास पर्याप्त थे? प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन की 75वीं सालगिरह के मौके पर अपने संबोधन में ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूएन महासभा के सामने कुछ सवाल रखे कि क्या प्रासंगिकता के मद्देनजर और मौजूदा हालात की चुनौतियों को देखते हुए यूएन के स्वरूप और ढांचे में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब यूएन की स्थापना की गई, भारत तभी से इसका सदस्य है।

उस दौर की दुनिया, समस्याएं, चुनौतियां आज से बिलकुल भिन्न थीं, लिहाजा आज यह सवाल सहज और स्वाभाविक नहीं है कि 21वीं सदी की दुनिया में यूएन कितना प्रासंगिक है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का सवाल था कि भारत यूएन के फैसले लेने वाले ढांचे का हिस्सा आखिर कब बनेगा? कब तक भारत को इंतजार करना पड़ेगा? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व की करीब 18 फीसदी आबादी भारत में बसती है। भारत समूचे विश्व को अपना परिवार मानता रहा है। इस देश में सैकड़ों बोलियां और विविधताएं हैं। भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया है और गुलामी का दौर भी देखा-सहा है। दुनिया के शांति मिशनों में भारत ने अपनी सेनाएं भेजी हैं और कई सैनिक 'शहीद' भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 40 करोड़ जन-धन बैंक खातों, 60 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना, 15 करोड़ घरों में पाइप से पेयजल पहुंचाने का अभियान, आयुष्मान भारत और करीब छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के प्रयासों आदि को 'आसान योजनाएं' नहीं माना जा सकता। भारत अब आत्मनिर्भर होने की दिशा में प्रयासरत है। विश्व स्तर पर सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस और योग दिवस भारत की ही उपलब्धियां हैं। सार यह है कि मानव-जाति के हित और कल्याण में हमेशा सोचने और काम करने वाले भारत को यूएन का स्थायी सदस्य आखिर कब बनाया जाएगा?

यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग और समर्थन अमरीका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका और साउथ कोरिया आदि देश करते रहे हैं, लेकिन यूएन में बदलाव करने की पहल भी नहीं की गई है। हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का 'अस्थायी सदस्य' चुना गया है। उसका दो साल का कार्यकाल जनवरी, 2021 में शुरू होगा। दरअसल आज भी संयुक्त राष्ट्र के पांच देश ही स्थायी सदस्य हैं-अमरीका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन देशों को ही 'वीटो पॉवर' हासिल है। यह ऐसा विशेषाधिकार है, जिसके तहत यूएन के महत्त्वपूर्ण फैसलों को भी बदला जा सकता है। यह यूएन की संकीर्णता है, लिहाजा मौजूदा तंत्र को बदला जाना चाहिए। भारत की ताकत को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विश्व की बड़ी शक्तियां भी महसूस कर रही हैं, लिहाजा अब यूएन के स्तर पर बदलाव को एक निरंतर अभियान बनाना चाहिए। कोरोना के संदर्भ में यह गौरतलब है कि भारत ने करीब 150 देशों को निशुल्क दवाएं मुहैया कराई थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वस्त किया है कि भारत में कोरोना का जो टीका बन रहा है और जिसका तीसरे चरण का परीक्षण जारी है, वह पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होगा। उसका उत्पादन और भंडारण उसी नजरिए से किया जाएगा। लेकिन बुनियादी विषय और चिंता यूएन से जुड़ी है, जिसकी प्रासंगिकता और प्रतिबद्धता ही सवालिया है।

हिंदी की स्थिति, गति और उपस्थिति

गिरीश्वर मिश्र

किसी भी देश के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भाषा बड़ी अहमियत रखती है। भाषा हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में दखल देती है। वह स्मृति को सुरक्षित रखते हुए एक ओर अतीत से जोड़े रखती है तो दूसरी ओर कल्पना और सर्जनात्मकता के सहारे अनागत भविष्य के बारे में सोचने और उसे रचने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

भारत भाषाओं की दृष्टि से अद्भुत देश है, जहां सोलह सौ से अधिक भाषाएं हैं। जिनमें भारतीय आर्य उपभाषा और द्रविड़ भाषा परिवारों की प्रमुखता है। ऐसे में द्विभाषिकता यहाँ की एक स्वाभाविक भाषाई व्यवहार रूप है और बहुभाषिकता भी काफी हद तक पाई जाती है। आर्य भाषा समूह में आने वाली हिंदी मध्य देश में प्रयुक्त भाषा समूह का नाम है। इसके बोलने वाले एक विशाल भू भाग में बिखरे हुए हैं। सामाजिक गतिशीलता के चलते यहां के लोग देश-विदेश में अनेक स्थानों पर पहुंचे। पर हिंदी के नाना रूप हैं जो उसकी बोलियों या सह भाषाओं में परिलक्षित होते हैं। साथ ही हिंदी का दूसरी भाषा के रूप में उपयोग करने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ी है। इसके विपरीत अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और बहुत थोड़े से लोगों की ही मातृभाषा है पर रुतबे के हिसाब से लाजवाब है।

यह भी अजब ऐतिहासिक संयोग है कि 'हिंदी' शब्द इस अर्थ में हिंदी भाषा का नहीं है क्योंकि यह भारत से बाहर के लोगों द्वारा भारतवासियों के लिए प्रयुक्त किया गया। कदाचित यह ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में मिलने वाले 'हेंदु' से जुड़ा है। मध्यकाल की ईरानी भाषा में 'हिंदीक' शब्द मिलता है। कहते हैं कि कभी गुजरात से भीतरी देश तक के विस्तृत क्षेत्र को हिंद प्रदेश माना जाता था और हिंदी शब्द देशबोधक था। जबाने हिंदी तो संस्कृत भाषा थी। बहुत समय तक हिंदी नाम की कोई अलग भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है अतः हिंद क्षेत्र की भाषा हिंदी है। सत्रहवीं सदी तक हिंदवी और हिंदी समानार्थी थे और मध्य देश की भाषा का अर्थ प्रदान करते थे। बीजापुर और गोलकुण्डा जैसे दक्षिण के राज्यों में भी दिल्ली और मेरठ की खड़ी बोली प्रचलित थी। इस तरह दक्षिण में 'दक्खिनी' हिंदी और उत्तर भारत की भाषा के लिए हिंदी का उपयोग होने लगा। अंग्रेजों के जमाने में हिंदवी वह भाषा बनी जो हिंदुस्तान के आमजनों की भाषा थी। इस तरह हिंदी समग्र देश से जुड़ी रही है।

भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण से संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के विविध रूपों का विकास चिह्नित हुआ है जो लगभग 1000 ईस्वी तक चला और तब शौरसेनी, नागर, अर्ध मागधी और मागधी अपभ्रंश से तमाम आधुनिक अर्य भाषाओं का उद्गम हुआ। ऐसे में क्षेत्रीय भिन्नताओं के मद्देनजर साहित्यिक और मौखिक रूपों वाली इंद्रधनुषी छटा वाली हिंदी पनपी। साहित्यिक उन्मेष की दृष्टि से ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी और खड़ी बोली अधिक समृद्ध हुई और अब खड़ी बोली प्रमुख हो चली है पर वह हिंदी के विविध भाषा रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। वही अकेली हिंदी नहीं है और उसकी ऊर्जा अन्य विभिन्न सहभाषाओं से आती है।

यह याद रखना होगा कि अंततः भाषा का लोक रूप यानी मौखिक व्यवहार ही केंद्रीय होता है और वह देश काल सापेक्ष होने से बदलता रहता है। आज छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, बघेली, अवधी, मगही, ब्रज, मैथिली, बुंदेली, जयपुरी, भोजपुरी, कुमाऊनी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, तथा खड़ी बोली आदि हिंदी के विविध रूप लोक प्रचलित हैं। उर्दू भी खड़ी बोली का ही रूप है जिसमें अरबी और फारसी का पुट है। अर्थात सिर्फ खड़ी बोली ही हिंदी नहीं है। राजनीति और लोभ लाभ की सहज मानवी प्रवृत्ति ने अनेक विवाद खड़े किए और वह प्रभुत्ववादी प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है जो हिंदी के वृहत्तर रूप को खंडित करती है।

ऐतिहासिक रूप से हिंदी भारत के लोक-जीवन से स्वाभाविक रूप से जुड़ी रही। स्वतंत्रता संग्राम में उसकी अखिल भारतीय भागीदारी ने उसे 'राष्ट्रभाषा' बना दिया। अंग्रेज सरकार सरकारी और शिक्षा के लिए अंग्रेजी को अधिकृत कर स्थापित कर चुकी थी और अफसरशाही अंग्रेजी और अंग्रेजियत का पर्याय बन चुकी थी। दूसरी ओर पराधीन भारत को स्वाधीन करने के लिए संग्राम का बिगुल बजाने में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की प्रजा के बीच जन भाषा की भूमिका थी। उनमें हिंदी का स्वर प्रमुख रहा और जनता से जुड़ने के प्रयास में हिंदी भारत में चतुर्दिक गूंजी। सहज सम्पर्क के लिए हिंदी स्वाभाविक माध्यम बनी। महाराष्ट्र हो या बंगाल, कश्मीर हो या गुजरात, पंजाब हो या दक्षिण भारत हर कहीं गणमान्य जन नेताओं ने हिंदी को अंगीकार किया। बापू ने 1917 में देश को सम्बोधित करते हुए कहा था- ''आज की पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़ें और हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कारवाइयां अपनी-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कारवाइयों की भाषा हिंदी होनी चाहिए।''

आगे चलकर हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने कई कदम भी उठाए। संविधान की रचना तक पहुंचते-पहुंचते भाषा और सरकार के बीच की समझ बदल गई और सरकारी कामकाज की भाषा यानी 'राजभाषा' (आफीशियल लैंग्वेज) का विचार अपनाया गया और जैसा कि संविधान का भाग 17 का अनुछेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि 'देवनागरी' ठहराई गई। राज भाषा शब्द को अपरिभाषित छोड़ दिया गया परंतु प्रशासनिक उद्देश्य से उसे जोड़ा गया। साथ ही अनुछेद 351 में हिंदी के विकास को संघ के कर्तव्य के रूप में दर्ज किया गया। इसके लिए राजभाषा विभाग बना और हिंदी फले-फूले इसके लिए तामझाम के साथ बहुत से उपक्रम शुरू हुए। राजभाषा नीति और उसके अनुपालन को लेकर सरकारी धींगामुश्ती होती रही। संविधान ने आठवीं सूची नामक एक विशेष और विलक्षण प्रावधान बनाया और 14 भाषाओं की एक सूची डाली। इस सूची का विस्तार होता रहा और अब इसमें 22 भाषाएं हैं। अभी 38 अन्य भाषाओं की ओर से गुहार है कि उनको भी इस सूची में शामिल कर लिया जाय हालांकि सूची में सदस्यता का भाषा के विकास के साथ कोई कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं दिखता।

1965 आते-आते हिंदी की राजभाषा का सवाल अनिश्चितकाल के लिए मुल्तबी हो गया क्योंकि वह सक्षम नहीं हो सकी थी और अंग्रेजी में कार्य करते रहने के लिए अनंतकाल की छूट ले ली गई। लोकतंत्र स्थापित होने पर भी सरकार चलाने के लिए अंग्रेजी की गुलामी बरकरार रही। इस बीच हिंदी के संस्थानों, समितियों, पुरस्कारों, अकादमियों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली सरकारी पहलों की फेहरिस्त लम्बी ही होती गई पर उनके क्षणिक उत्साहवर्धक और सीमित प्रभाव को छोड़कर उनका योगदान प्रायः असंतोषजनक रहा।

राजनीति के परिसर में भाषा ही नहीं कोई भी मुद्दा सत्ता और शक्ति के प्रयोजनों से जुड़कर ही अर्थवान होता है। इस हिसाब से यदि हिंदी हाशिए पर बनी रही तो कोई आश्चर्य नहीं। हिंदी की अनेक गैर सरकारी संस्थाओं का स्वास्थ्य अन्यान्य कारणों से गिरता गया। इधर भाषा प्रौद्योगिकी में चमत्कारिक बदलाव से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को जीवनदान मिला है और अब रचनात्मक अभिव्यक्ति का विराट विस्फोट हो रहा है। मीडिया, व्यापार जगत और मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में हिंदी की पकड़ मजबूत हुई है परंतु हड़बड़ी में हिंदी के हिंग्लिश होते जाने की चिंता भी सताने लगी है।

इस पूरे परिवेश में देश की ताजा शिक्षा नीति ने प्रकट रूप से मातृभाषा को सम्मान देने और अपनी भाषा में शिक्षा देने लेने के अवसर का एक खाका खींचा है। भाषा का प्रयोग अस्मिता और भावना के साथ जीवन में अवसरों की उपलब्धता से भी जुड़ी है। अंग्रेजी के सम्मोहन से उबरने के लिए स्वाभाविक हिंदी की जो समन्वय और लोक से जुड़कर जीवन पाती रही है, उसके उपयोग को बढ़ाना होगा। भाषाओं के भविष्य को लेकर जो चिंताएं आजकल व्यक्त की जा रही हैं उन्हें देखकर यह बेहद जरूरी हो गया है कि हिंदी के गौरव गान वाली समारोह की मानसिकता को छोड़कर हिंदी को ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्थ बनाया जाय।

(लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विवि, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

किसानों पर घटिया राजनीति

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

किसानों के बारे में लाए गए विधेयकों पर राज्यसभा में जिस तरह का हंगामा हुआ है, क्या इससे हमारी संसद की इज्जत बढ़ी है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है. पड़ोसी देशों के सांसद हमसे क्या सीखेंगे? विपक्षी सांसदों ने इन विधेयकों पर सार्थक बहस चलाने के बजाय राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश पर सीधा हमला बोल दिया. उनका माइक तोड़ दिया. नियम-पुस्तिका फाड़ दी. धक्का-मुक्की की. सदन में अफरा-तफरी मचा दी। उच्च सदन को निम्न कोटि का बाजार बना दिया।

यही विधेयक लोकसभा में भी पारित हुआ है लेकिन वहां तो ऐसा हुड़दंग नहीं हुआ। जिसे वरिष्ठ नेताओं का उच्च सदन कहा जाता है, उसके 8 सदस्यों को निलंबित करना पड़ जाए तो उसे आप सदन कहेंगे या अखाड़ा? विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि उपसभापति ने ध्वनिमत से इन किसान-कानूनों को पारित करके 'लोकतंत्र की हत्या' कर दी है, और सत्तारूढ़ दल के नेता इसे विपक्षियों की 'शुद्ध गुंडागर्दी' बता रहे हैं। यह ठीक है कि ध्वनि मत से प्रायः वे ही विधेयक पारित किए जाते हैं, जिन पर लगभग सर्वसम्मति-सी होती है।

यदि एक भी सांसद किसी विधेयक पर बाकायदा मतदान की मांग करे तो पीठासीन अध्यक्ष को मजबूरन मतदान करवाना पड़ता है. इस संसदीय नियम का पालन नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने इतना जबर्दस्त हंगामा मचाया कि सदन में अराजकता फैल गई। विपक्ष की सोच है कि यदि बाकायदा मतदान होता तो ये विधेयक कानून नहीं बन पाते. विपक्ष को पिछले 6 साल में यही मुद्दा हाथ लगा है, जिसके दम पर देश में गलतफहमी फैलाकर कोई आंदोलन खड़ा कर सकता है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने साफ-साफ कहा है कि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्यों, मंडियों और आड़तियों की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी लेकिन अब किसानों के लिए खुले बाजार के नए विकल्प भी खोले जा रहे हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े।

इस नए प्रयोग के लागू होने के पहले ही उसे बदनाम करने की कोशिश को घटिया राजनीति नहीं कहें तो क्या कहेंगे? सरकार ने 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 50 से 300 रुपये प्रति क्विन्टल की वृद्धि कर दी है। प्रसिद्ध किसान नेता स्व. शरद जोशी के लाखों अनुयायियों ने इस कानून के पक्ष में आंदोलन छेड़ दिया है। मेरी राय में ये दोनों आंदोलन इस समय अनावश्यक हैं। जरा सोचें कि कोई राजनीतिक दल देश के 50 करोड़ किसानों को लुटवाकर अपने पांव पर क्या कुल्हाड़ी मारना चाहेगा?

चाणक्य नीति

एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मुर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन-पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अतयंत घनिष्ठ सम्बन्ध बना लेता है।

काम की बात

क्रोध और आंधी दोनों बराबर शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है।

एक सलाह

मदद और मुस्कान ये दो ऐसे इत्र है जिन्हें जितना आप दूसरों पर छिड़केंगे, आपका जीवन उतना ही सुगंधित होता चला जाएगा।

ऐसे बदलेगी अन्नदाता की तकदीर

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

कृषि लागत और मूल्य आयोग ने पहली बार केन्द्र सरकार को खाद अनुदान की राशि सीधे किसानों को उनके खातों में उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। हालांकि इससे पहले इस आयोग द्वारा कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ही सुझाव प्रमुखता से दिया जाता रहा है। यह सुझाव इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह राशि सीधे किसान के पास जाएगी। आयोग ने सुझाव दिया है कि खाद अनुदान के रूप में यह राशि रबी और खरीफ फसल के लिए 2500-2500 रु. के अनुसार दो किस्तों में किसानों को दी जाए। सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को छह हजार रु. प्रतिवर्ष की राशि दी जा रही है। किसानों के लिए इस तरह साल भर में ग्यारह हजार रुपए मिलना बड़ी राहत होगी। निश्चित रूप से इससे किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इसमें दो राय नहीं कि यह अपने आप में अच्छा सुझाव है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित है तो उस दिशा में यह अग्रगामी कदम माना जा सकता है।

पिछले कुछ सालों से सरकारें चाहे केन्द्र की हो या राज्यों की, किसानों के प्रति संवेदनशील हो रही है। भले इसे वोटबैंक का कारण माना जाए। कोरोना ने खेती-किसानी के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। सरकारों को लोक लुभावन घोषणाओं के स्थान पर खेती-किसानी के लिए अब कुछ खास करना ही होगा। केन्द्र सरकार के किसानों के लिए लाए गए तीन विधेयकों को लेकर आलोचना-प्रत्यालोचना और राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण अलग-अलग राय हो सकती है पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अब समय आ गया है जब अन्नदाता की समस्या को समझना ही होगा। सरकारों द्वारा चुनावों के समय जिस तरह कृषि ऋण माफी की घोषणाएं की जाती है वह किसानों या यों कहें कि खेती-किसानी की समस्या का स्थाई हल हो ही नहीं सकता। हालांकि खाद अनुदान राशि और सम्मान निधि को देने का जो तरीका है उसको लेकर विचार किया जाना अभी भी आवश्यक है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की सहायता किसानों को अवश्य दी जानी चाहिए पर यदि खेती किसानी को बढ़ाना है और वास्तव में किसानों के भले के लिए सरकारें गंभीर हैं तो उसका सबसे बेहतर तरीका नकद राशि चाहे वह सीधे खाते में स्थानांतरित हो रही है उसके स्थान पर सरकार को आदान के रूप में उपलब्ध कराने से इसका सीधा लाभ अधिक प्रभावी तरीके से किसान और देश को प्राप्त होगा। भले सरकार राशि की सीमा यही रखे पर इस राशि की सीमा तक किसानों को उसकी मांग के अनुसार खाद-बीज उपलब्ध कराए जाते हैं तो उसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा। खाद-बीज मिलेगा तो किसान सीधे-सीधे इनका उपयोग खेत में करेगा और उससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने का फायदा प्रत्यक्ष रूप से किसान और देश दोनों को होगा।

देखा जाए तो किसानों के साथ खाद-बीज को लेकर अधिक ठगी होती है। नकली या घटिया बीज मिलने से किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसानों को जो बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, वे उच्च गुणवत्ता के साथ उनमें रोगनिरोधक क्षमता हो। इससे दोहरा लाभ होगा। किसानों को समय पर मांग के अनुसार बीज मिल जाएंगा तो दूसरी और उनकी प्रमाणिकता व गुणवत्ता में कोई संदेह नहीं रहेगा। ऐसे में उत्पादन बढ़ेगा और किसान को अधिक लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। इसके लिए भले ही सरकार राशि की सीमा पांच हजार ही रखे पर इतनी राशि के बीज-उर्वरक मिलेंगे तो इसका असर उत्पादकता पर पड़ेगा। इसे यों समझना होगा कि नकद राशि भले किसान को सीधे खाते में हस्तांतरित हो पर उसका उपयोग खेती-किसानी के लिए ही होगा, यह पक्का नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यदि प्रमाणिकता, गुणवत्ता और क्षेत्र विशेष की जरूरत के अनुसार इतनी राशि के कृषि आदान किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं तो यह किसान व देश दोनों के लिए ही फायदे का सौदा होगा।

वर्षों से खाद पर अनुदान सीधे उत्पादक कंपनियों को दिया जा रहा है। इसका सही लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। धनराशि का उपयोग खेती-किसानी में ही होगा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता लेकिन खाद-बीज वितरण के रूप में इस राशि का उपयोग किया जाएगा तो शत-प्रतिशत सही होगा कि उसका उपयोग खेत में ही होगा। सरकारी बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और इससे देश में अन्नधन का भंडार भरेगा। किसान की आय बढ़ेगी और सही मायने में खेती-किसानी का भला होगा। सरकारों को किसान की जरूरत की वस्तुएं अनुदान या निश्चित राशि तक की वस्तुएं उपलब्ध कराने की पहल करनी चाहिए। केन्द्र व राज्य सरकारों को इस दिशा में गंभीर होना होगा। कोरोना महामारी ने कृषि पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता महसूस करा दी है। ऐसे में नीति निर्माताओं को इस दिशा में चिंतन और मनन करना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

अभय-चेतना ही ईश्वरानुभूति

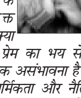

सुबह एक उपदेश सुना है। अनायास ही सुनने में आया है। एक साधु बोलते थे। मैं उस राह से निकलता तो सुन पड़ा। वे बोल रहे थे कि धार्मिक होने का मार्ग ईश्वर-भीरु होना है। जो ईश्वर से डरता है, वही धार्मिक है। भय ही उस पर प्रेम लाता है। श्भय बिनु होय न प्रीति।श् प्रेम भय के अभाव में असंभव है।

साधारणतया, जिन्हें धार्मिक कहा जाता है, वे शायद भय के कारण ही होते हैं। जिन्हें नैतिक कहा जता है, उनके आधार में भी भय होता है।

कांट ने कहा है, श्ईश्वर न हो तो भी उसका मानना आवश्यक है।श् यह भी शायद इसलिए है कि उसका भय लोगों को शुभ बनाता है।

मैं इन बातों को सुनता हूँ, तो हँसें बिना नहीं रहा जाता है। इतनी भ्रांत और असत्य शायद और कोई बात नहीं हो सकती है।

धर्म का भय से कोई संबंध नहीं है। धर्म तो अभय से उत्पन्न होता है।

प्रेम भी भय के साथ असंभव है। भय प्रेम कैसे पैदा कर सकता है? उससे तो केवल प्रेम का अभिनय ही पैदा हो सकता है। और अभिनय के पीछे अप्रेम के अतिरिक्त और क्या होगा? प्रेम का भय से पैदा होना एक असंभावना है।

वह धार्मिकता और नैतिकता जो भय पर आधारित होती हैं, सत्य नहीं मिथ्या है। वह आरोपण है, आत्मशक्ति का आरोहण नहीं। धर्म या प्रेम आरोपित नहीं किया जाता है। उसे तो जगाना होता है।

सत्य भय पर नहीं खड़ा होता है। वह सत्य के लिए आधार नहीं विरोध ही है। उसकी आधारशिला तो असंभव है।

धर्म और प्रेम के फूल अभय की भूमि में ही लगते हैं और भय में जो लगा लिए जाते हैं, वे फूल नहीं कागज के धोखे हैं।

ईश्वरानुभूति अभय में ही उपलब्ध होती है। या कि ठीक हो, यदि कहें कि अभय-चेतना ही ईश्वरानुभूति है। जिस क्षण समस्त भय-ग्रंथियां चित्त से विसर्जित हो जाती हैं, उस क्षण जो होता है, वही सत्य है।

राष्ट्रसंघ की भूमिका पर सवाल

अपनी उम्र से करीब छः साल बड़े संयुक्त राष्ट्रसंघ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी ने सवाल किया है कि पिछले पचहत्तर सालों में राष्ट्रसंघ में बदलाव क्यों नही आया, क्यों आज भी वह उसी समय के ढकोसलों और विचार धाराओं पर चल रहा है, मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के पचहत्तरवें साधारण अधिवेशन में इस वैश्विक संगठन की अब तक की भूमिका पर अनेक सवाल उठाए तथा पूछा कि इस लम्बी अवधि में आए वैश्विक संकटों के समय संयुक्त राष्ट्रसंघ की क्या भूमिका रही? इन संकटों से निपटने की दिशा में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने क्या किया, विशेषकर विश्वव्यापी आतंकवाद और कोरोना महामारी के समय? इन्हें रोकने और इनके जन्मदाताओं या संरक्षकों को दण्डित करने की दिशा में राष्ट्रसंघ ने क्या कार्यवाही की? मोदी ने भारत को लेकर भी सवाल उठाया कि राष्ट्रसंघ ने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की अब तक उपेक्षा क्यों की? उसे उसके यथोचित सहयोग से वंचित क्यों किया गया?

वैसे मोदी के भारत की उपेक्षा और राष्ट्रसंघ की अब तक की भूमिका को लेकर उठाए गए सवाल एकदम सही थे, उनकी वाणी से भारत की उपेक्षा का दर्द मुखरित भी हुआ, किंतु क्या इस तल्ख टिप्पणी भरे सवालों के पीछे मोदी की भावना महाशक्तियों को विशेष तवज्जोह देने की शिकायत भी छिपी थी क्या? और उनका यह कहना था कि पूरे विश्व में भारत आतंकवाद और मौजूदा कोरोना संकट से सबसे अधिक त्रस्त है और राष्ट्रसंघ तो ठीक महाशक्तियां भी इन दोनों संकटों के समय भारत के प्रति उदासीनता का रूख अपनाए हुए है।

अपने तर्कों के पक्ष में मोदी जी ने भारत में देशहित में मौजूदा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों व जनहितकारी योजना-परियोजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इस वैश्विक संगठन (राष्ट्रसंघ) को समय व उसकी आवश्यक्ता के अनुरूप चलना जरूरी है, क्योंकि विश्व के सभी सदस्य देश बड़ी आशाभरी निगाहों से राष्ट्रसंघ की ओर देख रहे हैं, इसके लिए राष्ट्रसंघ को अपनी पुरानी परम्पराओं व ढकोसलों को त्याग कर सभी सदस्य देशों की क्षमताओं को साथ लेकर चलना होगा, जिससे की वह सही अर्थों में सभी सदस्य देशों के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन कर सके और सभी देश आश्वस्त हो सकें।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तीन सप्ताह बाद (24 अक्टूबर को) राष्ट्रसंघ का पचहत्तरवां जन्मदिन आ रहा है और अगले साल भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने वाला है, इसलिए यदि यह कहा जाए अपरोक्ष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी नई भूमिका का एजेण्डा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, तो कतई गलत नहीं होगा? और यह तो विश्व के सभी देश जानते है कि विश्वव्यापी आतंकवाद को संरक्षक देने वाले पाकिस्तान और विश्व व्याप्त महामारी कोरोना के जन्मदाता चीन के खिलाफसंयुक्त राष्ट्रसंघ ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, ये दोनों देश भारत के कट्टर पारम्परिक विरोधी देश रहे है और आज भी है, ऐसे में इन दोनों विश्वव्यापी संकटों के हल की दिशा में संयुक्त राष्ट्रसंघ की निष्क्रीयता भारत के लिए चिंता व रोष का विषय तो है ही। इसलिए यदि मौके का फायदा उठाकर मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को उसका ही आईना दिखा दिया तो क्या गलत किया?

ओमप्रकाश मेहता लेखक

विश्व में अपनी प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए मोदी जी ने पूरे विश्व के सदस्य देशों को याद दिलाया कि विश्वव्यापी संकटों के समय भारत ने अपनी उपयोगिता किस तरह सिद्ध की, उनका कहना था कि भारत हमेशा से विश्वव्यापी आपदाओं के हल करने में अग्रणी रहा है, उन्होंने उदाहण दिया कि हाल ही में महामारी कोरोना के संकट काल में भारत ने करीब डेढ़ सौ देशों को अपने देश से औषधियां व अन्य रोग निरोधक वस्तुएं पहुंचाई, जबकि इस महामारी को पैदा करने वाला देश चीन मौन दर्शक बना रहा।

इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संक्षिप्त सम्बोधन में जहां राष्ट्रसंघ को उसके दायित्वों के साथ समय के साथ चलने की सीख भी दे दी, वहीं सदस्य देशों को भी पुरानी पटरी छोड़ नई पटरियों पर आने का परामर्श दे दिया।

कोरोनाः उम्मीद की किरण बनी स्टेम सेल थैरेपी

योगेश कुमार गोयल

कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए दुनियाभर के देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन सम्पूर्ण ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने तथा वैक्सीन मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध होने में अभी समय लगेगा। कई देशों में कोरोना के इलाज के लिए कुछ संभावित दवाओं या उपचार पद्धतियों के क्लीनिकल ट्रायल हो रहे हैं और कुछ में शुरूआती सफलता भी मिलती दिख रही है। कुछ देशों में 'स्टेम सेल थैरेपी' से भी कोरोना मरीजों का इलाज करने के प्रयास चल रहे हैं। यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) में तो इसी उपचार पद्धति से 73 कोरोना वायरस संक्रमितों को ठीक करने की सुखद खबर भी सामने आई थी। वहां के विदेश मंत्रालय के स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस विभाग की निदेशक हेंड अल कतीबा के अनुसार 'अबू धाबी स्टेम सेल सेंटर' (एडीएससीसी) ने 'स्टेम सेल थैरेपी' के जरिये कोरोना के सभी 73 कोरोना मरीजों को ठीक करने में सफलता प्राप्त की। अल कतीबा के मुताबिक इस रिसर्च सेंटर ने 'स्टेम सेल थैरेपी' से कोरोना इलाज की एक नई तकनीक 'गेम-चेंजर' विकसित की है, जिससे कोरोना संक्रमण को मात दी जा सकती है। इस नए इलाज में मरीज के रक्त से स्टेम सेल्स को निकालकर उन्हें फिर से सक्रिय करके रोगी के फेफड़ों में डाला जाता है। इससे फेफड़ों की कोशिकाओं को पुनर्जीवित किया जाता है, जिससे फेफड़ों की क्षमता पुनः बढ़ जाती है। यूएई की विदेश मंत्री हिंद अल ओतैबा के मुताबिक कोरोना महामारी से लड़ने में यह एक अभूतपूर्व कदम साबित हो सकता है। यूएई में जिन 73 मरीजों को यह उपचार दिया गया, उनमें से किसी भी मरीज ने तुरंत किसी साइड इफैक्ट्स की शिकायत नहीं की।

कुछ भारतीय शोधकर्ता भी 'स्टेम सेल थैरेपी' से कोरोना मरीजों के उपचार को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। कई भारतीय डॉक्टरों का मानना है कि शरीर में पाई जाने वाली मिजेंकाइमल स्टेम सेल्स कोरोना संक्रमित रोगी के क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः स्वस्थ कर सकती हैं क्योंकि स्टेम सेल्स का कार्य क्षतिग्रस्त टिश्यू की मरम्मत करना और नया टिश्यू बनाना है। भारतीय स्टेम सेल विशेषज्ञों के मुताबिक स्टेम सेल्स को रोगी या किसी स्वस्थ व्यक्ति से लेकर लैब में कल्चर कर एक निश्चित मात्रा में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डाला जाए तो मरीज ठीक हो सकता है। ग्रेटर नोएडा के डा. मधन जया रमन तथा डा. रश्मि जैन सहित देशभर के कुल 8 डॉक्टरों के समूह 'भारतीय स्टेम सेल स्टडी ग्रुप' ने 'स्टेम सेल थैरेपी' पर शोध करने के बाद दावा किया है कि कोरोना के मरीज स्वयं के स्टेम सेल से ठीक हो सकेंगे। इनका कहना है कि प्लासेंटा, अंबीलिकल कॉर्ड तथा बोन मैरो से निकलने वाले स्टेम सेल से कोरोना मरीज का उपचार किया जा सकता है। स्टेम सेल तीन प्रकार के होते हैं, भ्रूण स्टेम सेल (एंब्रियोनिक स्टेम सेल्स), व्यस्क स्टेम सेल (एडल्ट स्टेम सेल) तथा कॉर्ड स्टेम सेल।

डा. मधन का कहना है कि चीन तथा इजरायल में हुए शोधों से पता चला है कि प्लासेंटा (गर्भ में बच्चा जिस झिल्ली में रहता है) तथा अंबीलिकल कॉर्ड (गर्भनाल) से स्टेम सेल निकालकर कोरोना के मरीजों का उपचार किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीज की स्टेम सेल में कोरोना वायरस असर नहीं करता। इसीलिए स्टेम सेल्स ऐसे मरीज के रक्त में पहुंचकर बड़ी तेजी से अपनी तरह की कोशिकाओं को निर्मित कर मरीजों को ठीक कर सकते हैं। चीन में भी कुछ वैज्ञानिक कोरोना संक्रमित मरीजों के शरीर में मिजेंकाइमल स्टेम सेल्स डालकर अध्ययन कर चुके हैं। उस दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना संक्रमण के कारण जिन मरीजों को निमोनिया हुआ था, वे स्टेम सेल थैरेपी से उपचार के बाद स्वस्थ होने लगे। चीन के वुहान में स्टेम सेल थैरेपी विशेषज्ञ डा. डॉन्गचेंग वू ने भी स्टेम सेल ट्रीटमेंट से कोरोना वायरस के सफल इलाज का दावा किया है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जिस 'स्टेम सेल' थैरेपी की खोज की है, वह ऐसी थैरेपी है, जिससे बहुत से लाइलाज माने जाते रहे रोगों का इलाज संभव हो गया है। स्टेम सेल्स को शरीर की अनूठी कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, जिनमें टिश्यू (ऊतक) पुनर्जनन तथा मरम्मत की एक विलक्षण क्षमता होती है क्योंकि ये विशिष्ट सेल प्रकारों में स्वयं-नवीनीकरण तथा विभेद करने में सक्षम हैं। स्टेम सेल थैरेपी में स्टेम कोशिकाओं का उपयोग होता है, जो विभिन्न मूल से संबंधित विभिन्न कोशिकाओं में अंतर करने में सक्षम होती हैं। यह थैरेपी नए स्टेम कोशिकाओं के साथ घायल ऊतकों को बदलने पर केन्द्रित है। शरीर की रोगग्रस्त तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का स्थान लेकर स्टेम सेल उनमें नए जीवन का संचार करते हैं। चीनी स्टेम सेल विशेषज्ञ डा. डॉन्गचेंग वू के मुताबिक कोरोना के इलाज में स्टेम सेल थैरेपी इसीलिए कारगर है क्योंकि स्टेम सेल शरीर के खराब टिश्यूज की मरम्मत करते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि ये दूसरे टाइप के सेल में बदलकर खराब टिश्यू को ठीक कर सकते हैं।

स्टेम सेल थैरेपी ऐसी विधि है, जो विभिन्न प्रकार के स्टेम सेल का उपयोग कर चोटों तथा अन्य स्वास्थ्य की स्थिति में रोगों की एक विस्तृत श्रृंखला का इलाज करती है। यह थैरेपी मुख्य रूप से स्वस्थ और अनिर्दिष्ट स्टेम सेल्स के साथ घायल टिश्यूज को बदलने पर केन्द्रित है। यह ल्यूकेमिया, टिश्यू ग्राफ्ट्स, कैंसर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सेरेब्रल पॉल्सी, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्कलेरोसिस, विजुअल इंपेयरमेंट (आखों की बीमारी), ब्रेन इंजरी, मधुमेह, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, कार्डियाक मरीज, लकवा, हेपेटाइटिस, डीएनए डैमेज रिपेयर सहित कई असाध्य बीमारियों, चोटों तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के इलाज के लिए एक आशाजनक तरीका है। इसी स्टेम सेल थैरेपी का उपयोग कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में किया जा रहा है, जिसके प्रारंभिक नतीजे आशानुकूल रहे हैं। शोधकर्ताओं द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि अगले चरणों में इस थैरेपी के ट्रायल के सुखद नतीजे सामने आएंगे और यह कोरोना मरीजों के लिए कारगर साबित होगी।

कृषक आंदोलनः सरकार की विश्वसनीयता पर संदेह?

अपने 22 वर्षों पुराने तथा एनडीए के संस्थापक सहयोगी रहे अकाली दल के विरोध बावजूद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आनन-फानन में संसद के दोनों सदनों में देश के किसानों से संबंधित तीन कृषक अध्यादेश विवादित तरीके से पारित करा दिए गए। नतीजतन अकाली दाल ने न केवल अपने कोटे की खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल को मोदी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिलवाया बल्कि एन डी ए से समर्थन वापस लेने की घोषणा भी कर डाली। परन्तु सरकार यही कहे जा रही है कि नए कृषि कानून किसानों के जीवन में खुशहाली के नए रास्ते खोलेंगे। सरकार अध्यादेश रुपी इस कानून को किसानों के हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बता रही है। परन्तु देश का किसान इन नए कृषि कानूनों को न केवल किसान विरोधी बता रहा है बल्कि इसे किसानों के लिए 'मौत का फरमान' की संज्ञा भी दे रहा है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से यह अनुरोध भी किया है कि वे इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। इसी कानून के विरोध में गत 25 सितंबर को देश के कई बड़े राज्यों में किसानों ने व्यापक आंदोलन किये। रेल व सड़कें जाम की गईं। बाजार बंद कराए गए। देश के सौ से अधिक श्रमिक संगठनों के आव्हान पर 'अन्नदाता' सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। जब से नये कृषि विधेयक की चर्चा छिड़ी थी उसी समय से किसानों द्वारा इसका विरोध देश के अनेक भागों में शुरू कर दिया गया था। किसानों के तेवरों को देखकर यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किसान आंदोलन की यह आग शायद अभी थमने वाली भी नहीं है ।

केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध के प्रत्युत्तर में किसानों की समस्याओं व उनकी शिकायतों का वाजिब हल निकालने का आश्वासन देने के बजाए यह कहना शुरू किया कि विपक्षी पार्टियाँ किसानों को गुमराह कर रही हैं। किसान उनके द्वारा कृषक कानून के संबंध में फैलाये जा रहे झूठ व भ्रांतियों के बहकावे में आकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने लगभग पूरे देश के समाचार पत्रों में इसी आशय का संपूर्ण पृष्ठ का एक विज्ञापन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के साथ प्रकाशित कराया जिसमें किसानों व विपक्षी दलों की शंकाओं को 6 बिंदुओं में 'झूठ' शीर्षक के साथ काली पृष्ठभूमि में प्रकाशित किया गया तथा ठीक इसका सामने के भाग में 'सच' शीर्षक से इनका सकारात्मक पक्ष या यूँ कहें कि सरकारी पक्ष रखा गया है। इस पूरे पृष्ठ के विज्ञापन का मुख्य शीर्षक है 'किसानों,झूठ से सावधान -कृषि विधेयक ने किया है तरक्की का प्रावधान' । श्स्वतंत्र किसान-सशक्त किसानश् नारे के साथ जारी इस विज्ञापन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कथन भी प्रकाशित है जिसमें मोदी जी फरमाते हैं कि- '21 वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं,खुलकर खेती करेगा।21 वीं सदी का किसान जहाँ मन किया वहाँ फसल बेचेगा और जहाँ ज्यादा पैसे मिले वहीं पर फसल बेचेगा'।

उपरोक्त विज्ञापन सामग्री भारत सरकार के अर्थात जनता के करों के सैकड़ों करोड़ खर्च कर 23 सितंबर के समाचार पत्रों में तब प्रकाशित करवाई गयी जबकि देश की अधिकांश किसान यूनियन्स सरकार के इस नए कृषक कानून को 'किसान विरोधी काला कानून' बताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग को लेकर 25 सितंबर को भारत बंद का आव्हान कर चुकी थीं। सरकार ने केवल विज्ञापन ही प्रकाशित /प्रसारित नहीं कराए बल्कि अनेक प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों, कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों व अपनी विचारधारा के सैकड़ों स्तंभकारों व लेखकों से इस विधेयक के पक्ष में तथा आंदोलनकारियों व उनके समर्थकों के विरोध में स्तम्भ व आलेख भी प्रकाशित करवाए। स्वयं प्रधानमंत्री ने इस कानून के पक्ष में मोर्चा संभाला और कई जगह इस विधेयक का पक्ष रखते सुने गए। जाहिर है यह सारी की सारी कवायद सिर्फ इसीलिये थी ताकि या तो किसान अपना आंदोलन वापस ले लें या यह आंदोलन कमजोर पड़ जाए अथवा देश की किसान शक्ति विभाजित हो जाए। 21 सितंबर को सरकार की ओर से ऐसा ही एक प्रयास यह भी किया गया कि सरकार ने रबी की छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा भी कर दी। जबकि रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आम तौर पर सितंबर के बाद ही होती रही है। परन्तु किसानों के 25 सितंबर के भारत बंद व देश के विभिन्न भागों में हो रहे किसान आन्दोलनों को शांत करने के मकसद से सरकार ने संसद सत्र के दौरान ही इसकी भी घोषणा कर दी। अब किसानों के आंदोलन के बावजूद सरकार ने अपना दूसरा अभियान चलाने का फैसला किया है जिसके तहत आगामी 15 दिनों तक भाजपा कार्यकर्ता किसानों से व्यक्तिगत जनसंपर्क कर उन्हें नए कानून के सकारात्मक पहलुओं का 'ज्ञान' देंगे तथा उनकी शिकायतों को भी सुनेंगे।

उपरोक्त पूरे प्रकरण में काबिल-ए-गौर बात यह है कि जिस प्रकार सरकार विज्ञापन व आलेखों आदि के माध्यम से किसानों को समझाने पर इतनी ऊर्जा खर्च कर रही थी, देश के किसानों को नासमझ व दूसरे राजनैतिक दलों के बहकावे में आया हुआ बता रही थी इस कवायद के बजाए वह अपनी ही सरकार के प्रमुख सहयोगी अकाली दल व उनकी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल को यह बात क्यों नहीं समझा सकी कि यह कानून किसानों की तकदीर बदलने वाला है ? बादल परिवार केवल राजनैतिक परिवार ही नहीं बल्कि इस परिवार की गिनती पंजाब के चंद गिने चुने बड़े व संपन्न किसानों में भी होती है। आम गरीब किसानों की तरह यह परिवार कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ परिवार नहीं जिसे कोई राजनैतिक दल या नेता 'झूठ' बोलकर गुमराह कर दे ? यदि इस परिवार को ही इस किसान हितकारी कानून के फायदे बताने का जिम्मा दिया गया होता तो शायद पंजाब हरियाणा में आंदोलन की तीव्रता इस कद्र न होती जो 25 सितंबर को देखने को मिली ? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल का मोदी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना,अकाली दल का एनडीए से नाता तोड़ना और किसानों के साथ उनका खड़ा होना ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि यह कानून किसानों के हित में कम अहित में ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा होता कि किसानों को विज्ञापनों के माध्यम से संबोधित करने व विपक्षी दलों पर इस आंदोलन की भड़ास निकालने के बजाए अपने ही सहयोगी दलों व मंत्रियों तथा देश किसान संगठनों को विश्वास में लिया जाता।

तनवीर जाफरी

ऐसा प्रतीत होता है कि देश को मोदी सरकार की विश्वसनीयता के प्रति संदेह बढ़ता जा रहा है। नोट बंदी, जीएसटी, लॉकडाउन की घोर असफलता, अनियंत्रित मंहगाई, बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं व किसानों में पनपता असुरक्षा का वातावरण, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, चौपट हो चुके उद्योग धंधे, तेल से लेकर खाद्यान्न तक में आग लगाती मंहगाई, सीमाओं पर बिगड़ते माहौल जैसी अनेक बातों ने निश्चित रूप से सरकार के वादों, नीतियों व कथनों के प्रति विश्वास कम और सरकार की विश्वसनीयता पर संदेह अधिक खड़ा कर दिया है।

'गला फाड़ पत्रकारिता' टीआरपी की खातिर 'जूरा कुछ भी करेगा?'

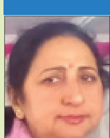

निर्मल रानी, लेखिका

जिस तरह भारतीय राजनीति इस समय देश के राजनैतिक इतिहास के सबसे संक्रमण कालीन दौर से गुजर रही है ठीक उसी तरह भारतीय मीडिया भी घोर संक्रमण काल से रूबरू है। टेलीविजन के शुरूआती दौर के जाने माने अनेक टी वी एंकर्स जैसे जे बी रमन,शम्मी नारंग,विनोद दुआ,प्रणव राय व प्रभु चावला आदि के दौर में शानदार व जिम्मेदाराना पत्रकारिता तथा बात चीत में शिष्टाचार, गंभीरता, चर्चा से संबंधित विषयों का संपूर्ण अध्ययन,आमंत्रित अतिथि के साथ शिष्ट व मधुर वातावरण में चर्चा आदि के दर्शन होते थे। निश्चित रूप से उपरोक्त एंकर्स व समाचार वाचकों को सुनने व देखने के लिए दर्शक व श्रोता उस समय की प्रतीक्षा करते थे जब इन्होंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता था। इनसे प्रभावित व प्रेरित होकर देश के लाखों होनहार युवाओं ने पत्रकारिता में अपना कैरियर भी बनाया। यही एंकर्स बड़े से बड़े लोगों के साक्षात्कार पूरी शालीनता व शिष्टाचार के साथ लिया करते थे। चीखना,चिल्लाना, पूर्वाग्रही पत्रकारिता करना,स्टूडियो को अदालत बनाते हुए कोई फैसला सुना देना,धर्म जाति के आधार पर कार्यक्रम तैयार कर देश के लोगों को बाँटना,उकसाना,दंगे फसाद भड़काने के लिए वातावरण तैयार करना जैसी बातों से ये परहेज करते थे। क्योंकि पत्रकारिता का धर्म, कर्तव्य व दायित्व इसकी इजाजत नहीं देते। परन्तु आज की टी वी पत्रकारिता तो आम तौर पर ऐसी हो चुकी है जिसे पत्रकारिता कहना भी गोया पत्रकारिता का अपमान है। ऐसे ऐसे चीखने चिल्लाने वाले लोग टाई सूट पहनकर स्टूडियो में बैठे हुए हैं जो पूरी तरह अपना मन बनाकर बल्कि अपने आकाओं से निर्देशित होकर किसी भी पूर्वाग्रही एजेंडे के साथ श्मदारी के जमूरे श् की तरह स्टूडियो में आते हैं। सच पूछिए तो आज के मुख्यधारा के इन एंकर्स का कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण का बेहूदा अंदाज व अपने अतिथियों के साथ बातचीत का इनका तौर तरीका व लहजा तथा इनके द्वारा किये जाने वाले शब्दों का चयन सुनकर तो कोई सज्जन अभिभावक अपने बच्चों को पत्रकारिता की शिक्षा भी नहीं दिलाना चाहेगा। इसी तरह के चीखने चिल्लाने वाले एंकर्स व इनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले भड़काऊ विषयों पर आधारित कार्यक्रमों ने टी वी से जनता का मोह तो भांग किया ही है,इससे विश्वास भी उठ गया है। पहले तो भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे कार्यक्रम के अतिथि प्रतिभागी ही टी वी डिबेट का चेहरा बिगाड़ने के जिम्मेदार समझे जाते थे। स्वयं अपनी पुरी लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बावजूद पूरे भारत के बहुसंख्यकों का पुरजोर तरीके से पक्ष रखने वाले डॉक्टर संबित पात्रा अपनी बात रखते हुए वैसे तो कभी कभी बड़े शालीन नजर आते हैं। परन्तु किसी मुसलमान धर्मगुरु को श्अबे मुल्लाश् कह कर संबोधित करना हो या इनके विचारों से मेल न खाने वाले हिन्दू धर्मगुरु को पाखंडी या कलयुगी धर्म गुरु कहकर बुलाने में यह देर नहीं लगते। 12 अगस्त को नोएडा में इन्हीं पात्रा साहब से एक परिचर्चा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। आजतक टी वी चौनल पर होने वाली इस परिचर्चा में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजीव त्यागी पर अमर्यादित जातिगत व धार्मिक टिप्पणी की थी तथा उन्हें अपमानित करते हुए अभद्र भाषा व अप शब्दों का इस्तेमाल किया था। संबित पात्रा ने राजीव त्यागी की ओर मुखातिब होकर गला फाड़ कर चिल्लाते हुए दहशत का वातावरण बनाया। इतना ही नहीं बल्कि चीखते चिल्लाते हुए पात्रा ने त्यागी को श्जयचन्दश् कहा व उन्हें नकली हिन्दू बताडाला। इन्हीं बाद कलामियों से आहत होकर राजीव त्यागी विचलित होने लगे। इसी दौरान पात्रा ने यह भी कह दिया कि माथे पर तिलक लगाकर कोई हिन्दू नहीं हो जाता। बस इसी के बाद राजीव त्यागी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया उन्हें उसी क्षण हृदयाघात लगा और परिचर्चा के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। राजीव त्यागी के देहांत के बाद व्यापक तौर पर संबित पात्रा की भाषा शैली की न केवल आलोचना की गयी बल्कि अनेक जगहों पर पात्रा के विरुद्ध प्रदर्शन हुए व उन्हें त्यागी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफकार्रवाई की मांग भी की गयी। परन्तु अब प्रतिभागियों से अधिक चीखने चिल्लाने व प्रतिभागियों को उकसाने यहाँ तक कि लाईव कार्यक्रम में जूता चप्पल चलाने व धक्का मुक्की के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने का जिम्मा खुद एंकर्स ने संभाल लिया है। चीखने चिल्लाने वाले एंकर्स की श्रेणी में अरनब गोस्वामी का नाम इस समय सबसे ऊपर है। कुछ लोग तो इनको मानसिक रोगी भी बता रहे हैं। अरनब जब गला फाड़ कर किसी पर बरसते,चीखते व चिल्लाते हैं तो वे किसी व्यक्ति के पद,उसकी मान मर्यादा,उसकी लोकप्रियता,मान सम्मान सब कुछ ताख पर रख देते हैं। महाराष्ट्र के निर्वाचित मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे,उनके गृह मंत्री व सांसद आदि को तो ऐसे संबोधित करते हैं जैसे कि वे बहुत बड़े अपराधी हों और अरनब न्यायाधीश। पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े विषय पर परिचर्चा के दौरान अरनब ने अकारण ही सलमान खान को खींच लिया जबकि वे अनुपस्थिति थे । अरनब चीख चीख कर गला फाड़ते हुए सलमान खान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे वह पत्रकार नहीं बल्कि श्मदारी का जमूराश् होने के लक्षण हैं। जरा सुनिए अरनब के बोल ---

'वह सलमान जो इतना बोलता था ना,कहाँ है ? कहां छिपा हुआ है ? ड्रग्स मफिया के बारे में आवाज क्यों नहीं उठती? बोलती बंद क्यों ? कहाँ है सलमान खान ? एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं एक ट्वीट नहीं ? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ हो सलमान ? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में सलमान ? देश की नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम तो बोल कर दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के, रट्टा मार के। तो क्यों न पूछूं मैं? अरे महानायक के लिए मेरी थोड़ी इज्जत है तो उनका नाम नहीं ले रहा मैं ,मगर सलमान की बोलती बंद क्यों?' कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की 'गला फाड़ एजेंडा पत्रकारिता' का मकसद अपने चौनल की टीआरपी अर्थात टारगेट रेटिंग पॉइंट को बढ़ाना है और इसकी खातिर टीवी चैनल्स के एक दो नहीं बल्कि अनेक 'जमूरे' कुछ भी करने को तैयार हैं ? परन्तु यह पत्रकारिता नहीं बल्कि पत्रकारिता के पावन पेशे को कलंकित व बदनाम करने के प्रयास हैं। देश-दुनिया व इतिहास ऐसे 'जमूरों' को कभी मुआफ नहीं करेगा।

न्यूज ब्रीफ

जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 33 सौ के पार

माही की गूंज, खरगोन। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते-बढ़ते अब यह आंकड़ा 33सो के पार पहुंच गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 53 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं 45 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए है। जबकि ग्राम बमनाला तहसील भीकनगांव निवासी 85 पुरूष की इंदौर के एमटीएच अस्पताल में उपचार के दौरान 29 सितंबर को मृत्यू हुई, इनका1 28 सितंबर को ही अस्पताल में उपचार कराया था और उसी दिन इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव 28 सितंबर को ही आई थी। इस तरह जिले में कुल कोरोना से संक्रमित 3 हजार 345 मरीज है। इनमें 2 हजार 853 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए, 43 की मृत्यू एवं 449 मरीज स्थिर है। पिछले 24 घंटे में 585 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा 476 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए है। जिले में कुल 247 कंटेनमेंट एरिया घोषित है।

गांधी जयंति पर कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश

माही की गूंज, खरगोन। गांधी जयंति के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा और महात्मा गांधी विषय पर व्याख्यान, परिचर्चा व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएं। इस आशय के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के निदेशक डॉ. उमेश कुमार सिंह ने समस्त शासकीय महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय व शसकीय उमावि के प्राचार्यों को दिए है। उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित करें।

ग्रामीण युवको के लिए निःशुल्क पुरुष टेलर प्रशिक्षण प्रारंभ होगा 5 अक्टूबर से

माही की गूंज, बड़वानी। स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी बड़वानी में 30 दिवसीय पुरुष टेलर प्रशिक्षण 5 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। उक्त प्रशिक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं बैंक ऑफइंडिया के संयुक्त तत्वाधान में होगा इस प्रशिक्षण में बड़वानी जिले के ग्रामीण युवक प्रतिभाग कर सकते है उक्त प्रशिक्षण 30 दिवसीय का रहेगा प्रशिक्षणार्थियों को आवास, भोजन और प्रशिक्षण सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी प्रशिक्षण में सीमित सीट होने के कारण 25 प्रतिभागी ही प्रतिभाग कर सकेंगे सीमित सीट होने के कारण अपना स्थान सुनिश्चित करने हेतु जल्द आवेदन करने हेतु हेल्पलाइन नंबर 7746000890, 9589565775 पर काल कर सकते है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंक सूची, 8 पासपोर्ट फोटो, पेन कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो), आय, जाति, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, समग्र आई डी, बैंक पासबुक।

कलेक्टर ने देखी वॉटर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉन की कार्यविधि

दोनों एजेंसी प्रस्तुत करेगी आगामी दिनों का प्लॉन

माही की गूंज, खरगोन।

शहर में सीवरेज व वॉटर सप्लाय का काम करने वाले दोनों एजेंसियां अक्टूबर सहित आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात इसी के आधार पर दोनों कंपनियां एक साथ खुदाई, पाईप बिछाना, कनेक्शन देना और रोड़ का समुचित तरीकें से भरण करने का कार्य करेगी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने बुधवार को शहर के इंटेकवेल वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट और खुदाई के बाद सड़क मरम्मत के कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरूआत उन्होंने कुंदा नदी पर बन रहे इंटेकवेल से की, इसके बाद वॉटर व सीवरेज ट्रीटमेंट का विस्तार से अवलोकन के पश्चात स्वामी विवेकानंद सभागृह में नपा के अधिकारी व दोनों एजेंसियों के इंजीनियर व ठेकेदारों के साथ बैठक की। बैठक में निरीक्षण किए गए स्थलों की जानकारी तथा आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने इंटेकवेल के बारे में जानकारी ली, यहां पर जरूरत से कम मजदूर कार्य पर देखकर बैठक में नाराजगी व्यक्त की। वहीं दोनों एजेंसियों से सितंबर का लक्ष्य और कार्य की जानकारी ली, लेकिन प्रस्तुत नहीं कर सकें। वॉटर सप्लाय व सीवरेज ट्रीटमेंट की विस्तार से समीक्षा 3 अक्टूबर को की जाएगी, इससे पूर्व दोनों एजेंसियों से कहा कि, आगामी समय में होने वाले कार्यों को लेकर अपनी-अपनी रूपरेखा प्रस्तुत करें। इसमें यह भी प्रस्तुत करें कि कितना कार्य हो चुका है और अब कितना कार्य दोनों एजेंसियों का बचा है, जिसे लेकर साथ में कार्य किया जा सके। आए दिनों खुदाई व मरम्मत के कार्य से आम नागरिकों को जा समस्या हो रही है, उससे मुक्ति दिलाई जाएं। बैठक में संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढ़ोके, नपा सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल, सरजू सांगले, प्रकाश चित्ते, कमलकांत जोशी सहित दोनों कंपनियों के प्रभारी इंचार्ज उपस्थित रहे।

3 एमएलडी सीवरेज का पानी पहुंच रहा है स्टेशन तक

सीवरेज व वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर श्रीमती पी ने सब स्टेशन के एक-एक पहलु को विस्तार से जाना। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के इंचार्ज नीरव पटेल ने ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जानकारी दी, उन्होंने बताया कि, किस तरह सीवरेज का वॉटर आने के बाद किन-किन प्रोसेस के माध्यम से क्लोरीनाजेशन की स्थिति से गुजरता है। उन्होंने बताया कि यहां फिलहाल 3 एमएलडी मिलीयन लीटर प्रतिदिन पहुंच रहा है। इसमें से 2 एमएलडी को ट्रीटेड किया जा रहा है। इंचार्ज पटेल ने सिवरेज के पानी के प्रायमरी, प्री, एसबीआर और क्लोरीनाजेशन स्तर तक की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

लेबोरेटी कक्ष का किया अवलोकन

वहीं कलेक्टर श्रीमती पी ने इस प्लांट में स्थापित किए गए लेबोरेटी कक्ष का भी अवलोकन किया। यहां इनलेट से आउटलेट तक सीओडी, बीओडी और टीएसएफतक की प्रक्रिया करने के बाद पानी के ऑक्सीजन और पीएच वेल्यू के प्रबंधन का कार्य भी जाना। लेबोरेटी प्रभारी राहुल वर्मा ने बताया कि, इस स्टेशन में आने वाले पानी का नाईट्रोजन, केमिकल और बॉयोलाजिकल रूप में ऑक्सीजन की उपस्थिति व अन्य तरह के तत्वों के बारे में ट्रीट कर जानकारी निकाली जाती है और प्रतिदिन यहां से एक एमएलडी पानी ट्रीट करने के बाद पुनः नदी में छोड़ा जा रहा है।

7 हजार घरों का कनेक्शन अब भी बाकी

सीवरेज ट्रीटमेंट व पाईप लाईन का कार्य कर रहे ठेकेदार पटेल ने बताया कि, शहर में कुल 111 किमी का सीवरेज कार्य किया जाना है, जिसमें अब केवल 3 किमी का कार्य होना बाकी है। शहर के कुल 13 हजार घरों का कनेक्शन किया जाना है, इनमें से 6 हजार घरों का कनेक्शन कर दिया गया है, अब भी 7 हजार घरों का कनेक्शन बाकी है। अभी फिलहाल अवनी ग्राम में इस प्रोजेक्ट के तहत पंपिंग स्टेशन बनकर तैयार हुआ है, यहां पंप इंस्ट्रॉल करना और 900 मीटर की पाईप लाईन का कनेक्शन होना बाकी है। पंपिंग स्टेशन के 40 किमी के दायरे का पानी यहां से पंपिंग किया जाएगा।

जिले के विभिन्न तहसीलों में राजस्व विभाग ने की कार्यवाहीं

माही की गूंज, खरगोन। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व विभाग ने कार्यवाही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी के निर्देशन में विभिन्न तहसीलों में राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वालों पर चालानी कार्यवाही, दुकानों पर गैस सिलेंडर, खाने-पीने की वस्तु सहित अन्य दुकानों पर कार्यवाही की गई।

कृषि महाविद्यालय खंडवा के अधिष्ठाता डॉ. भदौरिया ने किया कृषि विज्ञान केन्द्र का भ्रमण

माही की गूंज, बड़वानी। भगवंतराव कृषि महाविद्यालय खंडवा के अधिष्ठाता डॉ. यू.पी.एस.भदौरिया द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी का भ्रमण बुधवार को किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस.के. बड़ोदिया द्वारा डॉ. भदौरिया को केन्द्र द्वारा जिले में कृषि प्रसार की विभिन्न गतिविधियों जैसे कृषक प्रक्षेत्र प्रदर्षन, परीक्षण, फसल सघनता, मृदा परीक्षण, हाइड्रापोनिक्स, केंचुआ खाद के साथ-साथ विभिन्न प्रषिक्षण, प्रवासी मजदुरों हेतु आयोजित गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की जानकारी दी।

कृषि विज्ञान केन्द्र की प्रदर्शन इकाई पर स्थित फसल सग्रहांलय, केचुंआ खाद इकाई, ग्रीन नेट हाउस, डेयरी इकाई व कड़कनाथ इकाई का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान डॉ. भदौरिया द्वारा सुझाव दिए गए कि, जैविक खेती एवं समन्वित कृषि प्रणाली, कृषि की आधुनिक तकनीकों को प्रचार-प्रसार के द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि की जा सकती है। प्रक्षेत्र पर भ्रमण के दौरान फेन्सींग, वॉटर हार्वेस्टींग टेंक, खलिहानॅ इत्यादि की जानकारी ली। प्रक्षेत्र पर बीजोत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गई सोयाबीन व मूंग की फसल का अवलोकन किया। इस भ्रमण कार्यक्रम में केन्द्र के अधिकारी, कर्मचारी डॉ. एस.पी. त्रिपाठी, डॉ. डी.के. जैन, यू.एस. अवास्या, डॉ. डी.के. तिवारी, रविन्द्र सिकरवार एवं रंजीत बारा शामिल हुए।

कलेक्टर ने होम क्वारंटाइन पैसेंट से की वीडियो काल पर चर्चा

माही की गूंज, बड़वानी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बुधवार को कोविड कमाण्ड सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होने स्वयं, क्वारंटाइन कए लोगो से वीडियों कॉल करके उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त की, इस दौरान कलेक्टर ने वीडियो कॉल के माध्यम से जाना कि कोविड कमाण्ड सेंटर में नियुक्त चिकित्स उन लोगो से कब-कब चर्चा करते है, और क्या-क्या जानकारी प्राप्त करते है। कलेक्टरेट कार्यालय में स्थापित कोविड कमाण्ड सेंटर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने डाक्टरों से भी चर्चाकर जाना कि, वे वीडियो कॉल के माध्यम से किस प्रकार होम क्वारंटाइन किये गए लोगो से जानकारी प्राप्त करते है एवं उन्हें स्वास्थ्य सुविधा एवं सलाह देते है। ज्ञातव्य है कि, कलेक्टरेट कार्यालय में स्थापित कोविड कमाण्ड सेंटर में 24 घण्टे डाक्टरों की टीम नियुक्त की गई है, जो कोरोना पाजिटिव आए लोगो से वीडियो काल कर जानकारी प्राप्त करती है, जो होम क्वारंटाइन में रहकर अपना उपचार करवा रहे है।

कलेक्टर ने किया अपना कार्यालय, अपना घर अभियान के तहत कलेक्टरेट कार्यालय का निरीक्षण

माही की गूंज, बड़वानी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने उनके द्वारा प्रारंभ किए गए अपना कार्यालय, अपना घर अभियान के तहत कलेक्टरेट कार्यालय में संचालित विभिन्न कार्यालयो का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने संबंधित कार्यालय प्रमुखो से भी चर्चाकर जानकारी प्राप्त की, वही आवश्यक निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खुशी व्यक्त की कि, कोरोना के मददेनजर जिले में चलाए जा रहे अपना कार्यालय, अपना घर अभियान में सभी कार्यालय प्रमुख बढ़-चढ़कर भाग ले रहे है, जिससे कार्यालयों की रंगत एवं व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को बेहतर कार्य करने का वातावरण उपलब्ध करायेंगा, वहीं आने वाले आंगन्तुको को भी प्रेरणा देगा कि वे भी अपने घर एवं आस-पास साफ सफाई रखे। जिससे कोरोना वायरस की रोकथाम की व्यवस्थाओं में सभी का योगदान प्राप्त हो सके।

ज्ञातव्य है कि, कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले में अपना कार्यालय, अपना घर अभियान संचालित किया है, जिसके तहत कार्यालयो में साफ-सफाई का अभियान सफाईकर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रकार हुई साफ-सफाई का निरीक्षण अधिकारियों का दल कर नम्बरिंग देगा, जिस कार्यालय को सबसे ज्यादा नम्बर प्राप्त होंगे, उसे 2 अक्टूबर को प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

झाबुआ। शहर में मृत पाए जाने वाली गौ-माताओं के शव को लापरवाहीपूर्वक ट्रेचिंग ग्राउंड में फिकवाने को लेकर हिन्दू समाज तथा विभिन्न हिन्दू संगठन और गौरक्षक इस कृत्य का विरोध कर रहे है। इसी क्रम में मंगलवार को राष्ट्रीय हिन्दू सेना की जिला इकाई ने भी एकजुट होकर जिला मुख्यालय पर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एससडीएम एमएल मावलीय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन संगठन के प्रदेश संपर्क प्रमुख विरेन्द्रसिंह चौहान तथा जिलाध्यक्ष सौरभसिंह कंजेटा के नेतृत्व में सौंपा। जिसमें कहा गया कि शहर में मृत होने वाली गौ-माताओं को विधिपूर्वक दफनाने की प्रक्रिया की बजाय उनके शवों को ट्रेचिंग ग्राउंड में लापरवाहीपूर्वक फिकवाया जा रहा है। यह कृत्य हिन्दू संप्रदाय तथा गौ-भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। ज्ञापन में कहा कि राष्ट्रीय हिन्दू सेना इस कृत्य का घोर विरोध करती है तथा यह काफी निंदनीय है। इस तरह के कृत्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन एसडीएम मालवीय की ओर से संगठन को दिया गया। इस अवसर पर संगठन के नगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र सोलंकी, नगर मंत्री गौरव, अमित माली, सुनील आदि सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आदर्श महाविद्यालय में 1 से 30 अक्टूबर तक कक्षाओं का ऑनलाईन होगा संचालन

झाबुआ। शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ में आगामी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन जूम ऐप पर किया जाएगा। जो भी छात्र-छात्राएं आदर्श महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी है। वे जूम एप के माध्यम से जुड़ेंगे और इसकी लिंक से जुड़ने के लिए अपने विषय संबंधी प्रोफेसर से मोबाईल फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

संस्था के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एससी जैन ने बताया कि कॉलेज में आगामी 1 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन होगा। साथ ही वर्तमान में महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है। जिसमें 29 सितंबर के बाद तीसरे चरण अर्थात सीएलसी द्वितीय राउंड चलेगा। जो भी इच्छुक छात्र-छात्राएं है, वे बीए, बीकॉम, बीएससी में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है। महाविद्यालय में सभी विषयों के प्रोफेसर पदस्थ है। कॉलेज समस्त नवीन तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है।

मुख्यमंत्री के कोटेश्वर प्रवास पर झाबुआ जिले के वर्ग दो के उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे

माही की गूंज, झाबुआ।

बदनावर विधानसभा के कोटेश्वर पहुँचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने विगत दो साल के अधिक समय से रुकी पड़ी शिक्षक भर्ती की प्रकिया को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए, सीएम के काफिले को रोक कर नारेबाजी कर विरोध जताया और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर नोकरी देने की मांग करी। इस दौरान केवल धार जिले के ही नही झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम सहित आस पास के कई जिलो के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मार्ग पर लाइन से खड़े होकर हाथों में बेनर ओर पम्पलेट ले कर खड़े हो कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को देख शिवराज सिंह ने अपनी कार रोक कर वाहन से उतर कर अभ्यर्थियों की मांग को सुना और उनके दिए आवेंदन को लेकर इस पर उचित कदम उठाने की बात कही। अभ्यर्थियों द्वारा शुरू की गई नारेबाजी के बाद सीएम अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। बता दे पूर्व की शिवराज सरकार में वर्ग दो के लिए परीक्षा ली गई थी जिसके परिणाम बदली हुई कांग्रेस सरकार में आए, लेकिन तब से लेकर अब तक पास हुए अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नही हो सकी है जिसको लेकर पूरे प्रदेश के उत्तीर्ण अभ्यर्थी परेशान है और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मांग कर रहे हैं जिस पर दोनों सरकार ने अब तक कोई ध्यान नही दिया हैं। झाबुआ जिले से भी बड़ी संख्या में छात्र जिले का बेनर हाथ मे लिए अपनी मांगों को लेकर खड़े नजर आए जो विगत दो वर्षों से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

बच्चों के स्वास्थ्य की तरह वृद्धावस्था में वृद्धों के सेहत का भी रखें ख्याल

माही की गूंज, बड़वानी।

बाल्यकाल में जिस तरह बच्चों के पोषण उपचार का सूक्ष्मता से ध्यान रखा जाता है वैसा ही वृद्धावस्था में भी वृद्धों की सेहत का ध्यान परिजनों को रखना जरूरी है। किंतु प्रायः यह देखने व सुनने को मिलता है कि, हमें पोषित व शिक्षित करने वाले वृद्धजन उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह हमारी संस्कृति को विकृत बना देगा उक्त बातें सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत आशा ग्राम ट्रस्ट द्वारा संचालित अपना घर वृद्ध आश्रम में आयोजित वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य परीक्षण सह दंत चिकित्सा शिविर में डॉ एमएस सोलंकी ने कही।

उन्होंने वृद्धजनों का ब्लड प्रेशर चेक कर आवश्यक दवाइयां निःशुल्क प्रदान की इस दौरान पहाड़िया डेंटल केयर एवं रोटरी क्लब बड़वानी के सहयोग से दंत परीक्षण भी डॉ चक्रेश पहाड़िया के द्वारा किया गया, इस दौरान डॉक्टर पहाड़िया ने वृद्धों के दांतो को सुरक्षित रखने के लिए निःशुल्क दवाइयां एवं टूथपेस्ट का भी वितरण किया। उन्होंने बताया कि, वरिष्ठ जन अनुभव का सागर है तथा हमें इनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

इस दौरान मैनकाइंड कंपनी के प्रतिनिधि रितेश पाटीदार के द्वारा आवश्यक दवाइयां वृद्ध जनों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। शिविर में सम विकास सेवा संस्थान बड़वानी का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के स्वयंसेवक हिमांशु वाबले, अमित भावरे, प्रदीप किराड़े, फूल सिंह सिसोदिया, मित्र देव शर्मा, दूर सिंह गुथरे आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के रक्त बैंक एवं ओटी का किया निरीक्षण

माही की गूंज, बड़वानी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बुधवार को जिला चिकित्सालय के रक्त बैंक एवं ओटी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम घनश्याम धनगर भी थे।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रक्त बैंक के संचालक को निर्देशित किया कि, वे रक्त बैंक के बाहर अविलम्ब रक्त उपलब्धता संबंधित बोर्ड लगवायेंगे। जिसमें रक्त बैंक में उपलब्ध रक्त की उपलब्धता संबंधित समस्त जानकारी अंकित हो, जिससे पारदर्शित बनी रहे। इस दौरान उन्होने रक्तदान कर रहे युवाओं से भी चर्चाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इसी प्रकार कलेक्टर ने ओटी एवं मायनर ओटी का भी निरीक्षण कर मरीजो के चोटो का चल रहे उपचार को देखा एवं संबंधित पीड़ितो से चर्चाकर आवश्यक निर्देश संबंधित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को दिए।

कोरोना काल में घर बैठे सटोरियों की आईपीएल ने लौटाई रोनक

ऑनलाइन क्रिकेट सटोरियों ने जमाई अपनी-अपनी दुकानदारी

हाईटेक सट्टे से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की कोई तैयारी नही

माही की गूंज, पेटलावद।

कोरोना काल मे पिछले 6 माह से अधिक समय मे किसी प्रकार की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित नही होने से क्रिकेट के बुकी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। सबसे ज्यादा क्रिकेट की सट्टेबाजी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में होती है और इस खेल के बड़े बुकी पेटलावद में भी अपना खेल खेलते हैं। आईपीएल क्रिकेट को लेकर क्रिकेट के सटोरियों द्वारा लंबे समय से इंतजार रहता है और आईपीएल क्रिकेट के मोबाइल से ऑनलाइन सटोरियों ने क्रिकेट शुरू होने के पूर्व से ही अपनी दुकानदारी जमा ली थी, पूरी तरह से क्रिकेट का सट्टा हाईटेक हो चुका है जिस तक पुलिस तब ही पहुँच सकती है जब इस गोरख कारोबार के कीड़ों को मारने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था नही है जिससे हाईटेक क्रिकेट सटोरियों को दबोचा जा सके और उसकी न कोई तैयारी है। वही छोटी-मोटी सूचना को पुलिस हल्के में लेकर खानापूर्ति कर दबा देती है, फिलहाल तो सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन क्रिकेट सटोरियो द्वारा अपनी दुकानदारी जमा ली है, जो नगर के बड़े-बड़े रसूखदारों के माध्यम से चल रही हैं, जिसके तार नगरों, महानगरो, राज्य स्तरीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए हैं। 19 सितंबर को आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है, परंतु उसके पूर्व ही क्रिकेट के मोबाइल से क्रिकेट सट्टा खेलने वालों ने अपनी-अपनी दुकानदारी जमा ली थी एवं बड़े स्तर से लाखों-करोड़ों में सट्टा खेले जाने का अनुमान है, कई सटोरियों द्वारा पहले से रणनीति बना ली है कि, इस बार हमें क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे में कितने करोड़ रुपए कमांना है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार पूर्व में भी नगर में कुछ सटोरियों द्वारा करोड़ों रुपए का मोबाइल से क्रिकेट सट्टा कर कमाए जाने की जन चर्चा है और सटोरियो द्वारा कुछ संपत्तियां भी अर्जित की जा चुकी है जहां आज तक किसी बड़े अधिकारी की नजर ऐसे कुख्यात सटोरियों पर नहीं पहुंच पाई है। आखिर क्या कारण है कि, इतने बड़े स्तर पर सटोरियों द्वारा करोड़ों रुपए की अचूक संपत्ति कर ली गई है, उसके बावजूद भी वे शासन-प्रशासन के घेरे में नहीं आए हैं। जबकि सट्टा एक सामाजिक बुराई मानी जाती है उसके बावजूद भी इतने बड़े स्तर पर अवैध रूप से जुए-सट्टे का कारोबार चलना आखिर किसके संरक्षण में फलता-फूलता है? यह एक जांच का विषय है। एक नहीं कई स्थानों पर ऐसे अवैध गोरखधंधे देखे जा सकते हैं। देखना है कि, नगर में कितने मोबाइल क्रिकेट सट्टा धारकों के खिलाफबड़े स्तर पर कार्रवाई की जाती है। क्योंकि पूर्व में भी बताया जाता है कि, एक रसूखदार धनाढ्य व्यक्ति द्वारा नगर के युवकों से लाखों रुपए क्रिकेट के सट्टे में हार कर बर्बाद हो गए फिलहाल तो मोबाइल से ऑनलाइन क्रिकेट

सटोरियों की पौबारह हो रही है। नगर में सट्टे से जुड़े बड़े-बड़े प्रकरण सामने आ चुके हैं जिसमे बर्बाद हो चुके युवा मौत को तक गले लगा चुके हैं तो कई किसानों की फसल की लाखों रुपए व्यापारी से सट्टे की भेंट चढ़ने का मामला जिसमे नगर में सट्टे की ट्रेल से जुड़े बड़े धन्ना सेठो की नामजद शिकायत हो चुकी है लेकिन इन सटोरियों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि, पुलिस की पेड़ी पर पहुँच कर भी बेदाग वापस लौट आए और पेटलावद की रगो से सट्टे के नासूर को खत्म करने का एक सुनहरा अवसर भी गवा दिया जिसके पीछे बड़ी लेंन-देन की जन चर्चा आम तक हुई।

हर गली हर नुक्कड़ पर पाना भरने वाले मौजूद

नगर की बात करे तो क्रिकेट के अलावा अखर पत्ती का अंको वाला काला कारोबार आज भी नगर के हर गली, नुक्कड़ पर चल रहा है और नगर को इस धंधे में इतनी महारत हासिल हो गई कि, केवल पेटलावद ही नही आस-पास के जिलों और राज्यो तक का पूरा कारोबार पेटलावद ओर धार जिले के कुक्षी में जमा होता हैं, कई बाहरी सटोरिये यहाँ आकर हाथ आजमा चुके हैं लेकिन यहाँ कुछ लोगो के इर्द-गिर्द चलने वाला पूरे खेल पर एक क्षत्र राज है जिसका खामियाजा बहारी लोग बर्बाद हो कर उठा चुके हैं।

सब बन्दी का खेल, परिवार विशेष के इर्द-गिर्द घूम रहा पूरा खेल

कहा जाता है अवैध शराब और सट्टे के खेल को कोई बन्द नही कर सकता क्योंकि की इससे जुड़े अवैध धंदेबाज बड़े स्तर तक भेंट पूजा करते हैं जिसके चलते बड़े स्तर पर कोई कार्यवाही नही हुई और मामले में केवल छोटे-छोटे लोगो पर प्रकरण बना कर खाना पुर्ति की जाती हैं। बात करे पेटलावद की तो यहाँ सट्टा बाजार एक ही परिवार के इर्दगिर्द घूम रहा है मानो कोई पुश्तेनी संपत्ति हो और उसका बटवारा किया गया सब ने अलग-अलग लाइन के सट्टे की राह पकड़ ली, एक अंको का जादूगर है तो दूसरा वायदा बाजार का तो तीसरा क्रिकेट का महारथी कम समय मे इनकी सम्पन्नता से प्रभावित होकर नगर के कुछ और पूंजीपति भी इस मैदान में उतर गए है। इस खेल के ये पुराने खिलाड़ी विशेष पुलिसिंग के प्रयास से पकड़े जा सकते है।

ईमानदारी और हाईटेक तरीके से ही पकड़ा जा सकता है पूरा खेल

इस खेल और खेल खिलाड़ियों से पुलिस भी अनभिज्ञ नही है लेकिन जब भी बात इस धंधे की होती है तो, पुलिस केवल इतना बोलकर पल्ला झाड़ लेती हैं कि, आप जानकारी दो हम पकड़ लेगे, जबकि पूरा खेल अब हाईटेक हो चुका है जहां पहले पर्ची का उपयोग होता था वही अब पूरा खेल मोबाइल में सिमट गया हैं, जितने भी लोग इस धंधे से जुड़े हैं मोबाइल का पूरा उपयोग करते हैं, यदि पुलिस मामले में ईमानदारी और हाईटेक तरीके से खबरियों को लगा कर संदिग्धों के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रिकॉर्डिंग करे तो पूरे मायाजाल का बड़ा भंडाफोड़ हो सकता है, पुलिस कभी ऐसा करेगी इस पर भी संशय हैं।

किसान सम्मान निधि में नाम जोड़ने के लिए चल रही थी वसुली

ग्रामीणों ने दिया पटवारी के खिलाफ आवेदन

माही की गूंज, पेटलावद।

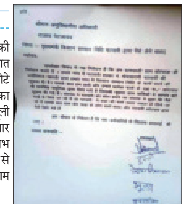

राजस्व विभाग से पैसे की लेंन-देन कर काम करने की बात तो आम है, राजस्व के छोटे-मोटे काम निपटाने के लिए हल्का पटवारीयो द्वारा ग्रामीणों से वसूली की जाती रही है तो कई बार शासन की योजना के लाभ दिलाने के लिए भी ग्रामीणों से बिना पैसे वसूल किए कोई काम नही होता है यह सार्वजनिक हैं।

ऐसा ही एक मामला पेटलावद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत मोईचारणी में सामने आया, जहा मोईचारणी हल्के के पटवारी ने ग्राम बोरपाडा के किसानों से किसान सम्मान निधि योजना में नाम जोड़ने के लिए 100-100 रुपए प्रति किसान वसूल लिए, जिसका कोई प्रावधान नही है। मामले की जानकारी बोरपाड़ा के किसानों ने मोईचारणी ग्राम पंचायत सरपंच को दी, जिस पर सरपंच में पटवारी से 100-100 रुपए प्रत्येक किसान से वसूलने का कारण जानने की कोशिश की तो, पटवारी का कहना था कि, खाता नकल के लिए पैसे लिए जा रहे हैं।

सरपंच छगन गामड़ का कहना है कि, ऐसा कोई प्रावधान नही है की किसानों से पैसे लिए जाए।

पटवारी ने मेसेज भेज कर कहा करवा दो ट्रांसफर, ग्रामीणों ने दिया आवेदन

सरपंच छगन गामड़ ने पटवारी को फोन लगाने के बाद पटवारी ज्योतिराज खराड़ी ने सरपंच के मोबाइल पर वाट्सएप मेसेज भेजते हुए लिख कर पहुँचाया कि, आप सांसद महोदय से मेरी शिकायत कर मोईचारणी से हटवा दो मुझे आपकी पंचायत में काम नही करना। पटवारी द्वारा पूरे बोरपाडा गाव के लोगो से वसूली करने से नाराज ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद को आवेदन दिया जिसमें पटवारी ज्योतिराज खराड़ी के साथ चौकीदार पर भी वसुली का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की।

गम्भीर स्थिति में पहुँचा पुलिया, बड़ी दुर्घटना को दे रहा है आमंत्रण

माही की गूंज, बनी। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से इंदौर-अहमदाबाद फोर लाईन से पेटलावद-रतलाम को जोड़ने वाली पुलिया धंसने की कगार पर आ गया है। जल्द इसे दुरुस्त करने के बजाय बेरिकेड्स लगाकर आवाजाही नहीं रोकी जा रही है। लेकिन इस इलाके के लोगों के आवागमन का यही एक शार्टकट होने के कारण एवं प्रसिद्ध मंदिर विश्व मंगल धाम पर आने वाले दर्शनार्थी निकलते हैं। इस अव्यवस्था के चलते यह जर्जर पुलिया कभी भी धंस सकता है। हादसे की आशंका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने वहां पर कुछ समय पूर्व चेतावनी का बोर्ड और बैरिकेड्स लगाकर अपने काम की इतिश्री कर ली। लेकिन लोगों ने बैरिकेड्स हटाकर वाहन निकालना शुरू कर दिया है। यदा-कदा रात में भारी वाहन भी इस पुलिया से गुजरते हैं। अगर ऐसे में जर्जर पुलिया धंस गया तो जान-माल की भारी क्षति हो सकती है। जिम्मेदार इस जर्जर पुलिया को दुरुस्त करवाना तो दूर, देखना तक मुनासिब नहीं समझ रहे। शायद उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इस बारे में पेटलावद लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करना चाहा लेकिन मोबाइल अटेंड नही हुआ।

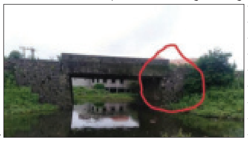

स्वास्थ्य विभाग में जमकर हो रही है लीपापोती

भवन की मरम्मत व शौचालय का हो रहा घटिया निर्माण

माही की गूंज, भामल। नारायण पालरा

देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि, न खाऊंगा न खाने दूंगा अपना उद्बोधन देते हुए कहते हैं कि, मैं भ्रष्टाचार कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन जब धरातल व ग्रामीण अंचलों में शासन के माध्यम से ग्रामीणजनों की योजनाओं का पैसा ठेकेदार व विभागीय अधिकारी खुद ही भ्रष्टाचार कर डकार रहे हैं।

बतादे कि, झाबुआ जिले में प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में सभी नवनिर्मित निर्माण आरोग्य केंद्र स्थापित करना है, जिसमें नवीन भवन नहीं हो वहां नया भवन बनवाया जाए, तो वही पुराना भवन होने पर उसे रिपेयर करके लाइट फिटिंग वह शौचालय आदि सुविधाएं उप स्वास्थ्य केंद्र पर मिले, इसी उद्देश्य से शासन करोड़ों का बजट पास करके निर्माण किया जा रहा है। तो वही ठेकेदार हाई लेवल के होने के कारण व राजनेतिक दबदबा होने की वजह से इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। हमने पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत करवाया था लेकिन फिर भी भ्रष्टतंत्र व इसके आला अधिकारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया को ही गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पूर्व में भी हमने भामल सहित कलदेला आरोग्य केंद्र के भ्रष्टाचार की नब्ज टटोलकर उसे जनहित के मुद्दे को लेकर जनता के सामने रखा था लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई नही करते हुए आज भी उसी ठेकेदार को निर्माण कार्य की अनुमति दे दी गयी।

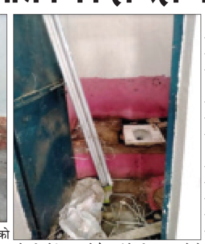

प्रदेश सरकार से लेकर राज्य सरकार करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग में प्रतिवर्ष आवंटित करती है। लेकिन मॉनिटरिंग करने वाले जिम्मेदार अधिकारी व इंजीनियर अपना हित साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ ऐसा ही मामला थांदला जनपद के अंतर्गत सागवा ग्राम पंचायत में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखी जा सकती है, जिसमें दरवाजे से लेकर निर्माण कार्य घटिया किस्म का किया जा रहां है नवनिर्मित ठेकेदार अपना हित साधने के लिए घटिया निर्माण कर के लाखो की चपत लगा रहा है।

प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप क्रय के लिए 60 लाख 50 हजार रूपए बैंक खातों में डाले

माही की गूंज, रतलाम।

शासन की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शुक्रवार को जिले के 242 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 25-25 हजार रूपए कुल 60 लाख 50 हजार रूपए बैंक खातों में डाले गए। रतलाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थि उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा शीतल कसेरा, नाहर कान्वेंट स्कूल के छात्र हार्दिक अग्रवाल, गुरु रामदास पब्लिक स्कूल की छात्रा अशफिया खान, गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल के छात्र प्रियांश भंडारी, गुरु तेग बहादुर स्कूल की छात्रा समीक्षा मोगरा को अतिथियों के हाथों प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए।

इस अवसर पर कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, जिला शिक्षा अधिकारी के.सी. शर्मा, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुभाष कुमावत, जिला पंचायत अध्यक्ष परमेश मईडा के साथ विद्यार्थी तथा उनके पालक उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया।

उल्लेखनीय है कि, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा बारहवीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत एवं उससे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय करने के लिए शासन द्वारा 25-25 हजार रूपए की राशि प्रदान की जा रही है। रतलाम जिले में उक्त योजना से कुल 562 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, शेष विद्यार्थियों के खातों में भी बैंक खाता नंबर सत्यापित करने की प्रक्रिया पश्चात राशि अंतरित की जाएगी।

संसद-विधायक प्रतिनिधि एक ही गाँव के, दोनों दल मिल कर करते है राजनीति, फिर भी नगर की दशा खराब

सभी जवाबदारो की अनदेखी के कारण झकनावदा-राजगढ़ रोड बना तालाब

माही की गूंज, झकनावदा।

पेटलावद विकास खण्ड की बड़ी ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत झकनावदा जो कि पेटलावद की राजनीति के दुसरे छोर का केंद्र बिंदु माना जाता है, यहाँ दोनों मुख्य दलों के बीच हमेशा सामंजस्य की राजनीति देखी जाती है। भाजपा के आयोजनों में कोंग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के आयोजनों में भाजपा के नेता बड़ी शिद्दत से सहभागिता करते देखे जाते हैं, चुनाव के दौरान भी एक धड़ा मिल कर तय करता है कि, किसके पक्ष में कार्य करना है, जिसमे दोनों दल के नेता किसके पक्ष में कार्य करना है तय करके अपनी-अपनी पार्टी के साथ दगा करने से भी नही चूकते, ऐसे झकनावदा गाँव मे जहा वर्तमान में सांसद के प्रतिनिधि और विधायक के प्रतिनिधि रहते हैं उस गाँव मे विकास की जगह कीचड़ की गंगा मुख्य मार्ग पर बह रही हैं।

गंभीर स्थिति में झकनावदा के मुख्य बस स्टेशन और मुख्य झकनावद-राजगढ़ की गंभीर स्थिति।

जी हां हम बात कर रहे हैं पेटलावद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झकनावदा से लगे हुए झकनावदा-राजगढ़ रोड की जहां पर वर्षा होते ही रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं यह स्थिति मेन बस स्टैंड से लगाकर ग्राम पंचायत तक देखी जा सकती है इस प्रकार की स्थिति को विकराल रूप में देखने के लिए आपको ग्राम पंचायत से थोड़ा आगे मोड में आना पड़ेगा जहां पर एक छोटे तालाब नुमा दृश्य दिखाई देगा। आपको बता दें कि, जहां पर रहवासी इलाका है, ऐसा नही की ये हालत केवल बारिश में होती हैं 12 माह कई घरों का गंदा पानी नाली नही होने से सीधा सड़क पर आता है जिससे बर्षभर ये स्थिति बनी रहती है। इस समय देश कोरोना संकट काल से जूझ रहा है ऐसे में बीमारी का बढ़ना लाजमी है क्योंकि कोरोना वायरस नमी वाले स्थानों पर अधिक फैलता है इस तालाब नुमा रोड पर गंदे पानी का जमाव लगातार बना हुआ रहता है एवं कीचड़ भी है ऐसे में दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन वाले लोगों का इस रोड से निकलना दुश्वार हो गया। बसों का संचालन भी लगभग शुरू हो गया है ऐसे में बसों के टायर फूटना एवं दुर्घटना होना लाजमी है, इसी क्रम में ग्राम पंचायत झकनावदा से करीब 40 गांव लगे हुए हैं और 40 गांव के लोग इसी रोड से अपना जरूरी सामान लाने ले जाने का काम करते हैं, कभी-कभी तो इस गड्ढे से भरे हुए कीचड़ में गिर जाते हैं, रोड की खस्ता हालत को लेकर जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों सहित जिले के बड़े अधिकारियों को भी मामले की जानकारी है, वर्तमान कलेक्टर सड़क पर पड़े गड्डो को भरने के लिये जरूरी निर्देश भी जारी कर चुके हैं लेकिन इस दिशा में कोई एक्शन नहीं लिया और लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों दोनों रोड की खस्ता हालत से पल्ला झाड़ कर एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि, हम लगातार सबंधित विभाग के अधिकारियों को इस समस्या को लेकर अवगत करवा रहे हैं लेकिन सफाई और आवश्वासन ही देते रहे है।

पंचायत ने नही खोदने दी नाली, इसलिए खराब हुआ रोड

मामले में ऐसी जानकारी मिल रही हैं कि, लोक निर्माण विभाग का काम है ओर विभाग अब इस दुर्गति के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदार बता रहा है और उससे निराकरण करने की बात कर रहा है। विभाग का कहना है कि, जब इस रोड का निर्माण हुआ तब हमने ग्राम पंचायत को एक लेटर के माध्यम से अवगत करवाया था कि, आप हमें नाली खोदकर दे दीजिए हम उसमें इस गंदे पानी की निकासी करने के लिए पाइप लाइन डाल देंगे, परंतु उन्होंने हमारी एक न सुनी, विभाग और पंचायत के बीच उलझा रोड बिलकुल खराब हो गया है स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल फोटो सेशन में लगे हैं जिन्हें गाव की दुर्दशा से कोई सरोकार नही है। रोड से गुजरने वाले स्थानीय लोग अब चुटकी लेने लगे हैं ये की इस गाँव मे सांसद और विधायक प्रतिनिधि रहते हैं इसलिए इस गाँव को स्मार्ट सिटी बनाया गया है जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आएगे।

हिंदू युवा जनजाति संगठन ने दिया ज्ञापन, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग

माही की गूंज, झाबुआ। हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिलाध्यक्ष कमलेश मावी पर सोमवार को उनके गृह गांव अंबा पीथमपुर में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई थी, अज्ञात व्यक्तियों ने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा था। जानकारी के अनुसार कमलेश ने मंदिर मे जाकर अपनी जान बचाई। इस घटना को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेघनगर एसडीएम एनएल गर्ग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की साथ ही घटना की निंदा की। हिंदू युवा जनजाति संगठन के झाबुआ जिला अध्यक्ष कमलेश मावी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी की। इसके अलावा संगठन के कार्यकर्ताओ नें थांदला थाना प्रभारी विवेक कुमार शर्मा को भी ज्ञापन दिया। बता दे कि, संगठन जिले में धर्मान्तरण का कडा विरोध कर रहा है एंव आये दिन जिलाध्यक्ष कमलेश मावी आनाज घोटाले की जांच कराने की मांग करते आए है। मेघनगर एसडीएम को ज्ञापन देते समय कैलाश निनामा, रायमल पारगी, गणेश वसुनिया, सुनील डामोर, रतन गणावा, दीवान निनामा, विजय गुडिया, अरविंद कटारा, विजय सिंगाड, नवल चारेल, रवि वसुनिया, अक्कू गणावा, रोहित प्रजापत, राजू वसुनिया, राहुल भूरिया, दिनेश भूरिया, संतोष, कमल बारिया आदि संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

हत्या कर चंबल नदी में शव फैकने वाले हत्याकांड का खुलासा, 5 दिन में 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में

बहन पर रखता था गलत नियत, भाई ने साथियों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

माही की गूंज, रतलाम। राघवेंद्र सिंह डोडिया

जिले में 20 सितम्बर को ग्राम बरखेड़ा कला के पास चंबल नदी में एक शव तैरता हुआ मिला था जिसके शरीर पर कोई कपड़े नही थे शरीर पर पहचान के कुछ चिन्ह थे। उक्त शव काफी पुराना होकर जीर्ण-शीर्ण हो रहा था जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे। शव की पहचान की जाना काफी मुश्किल हो रहा था। जिस पर थाना बरखेड़ा कला जिला रतलाम पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।

थाना प्रभारी बरखेड़ा उनि विजय सनस व थाना प्रभारी ताल उनि अमित सारस्वत के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा घटना स्थल व उसके आस-पास की जगह का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर साक्ष्य का संकलन किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक के शव के फोटो को प्रसारित किया गया, जिससे उक्त शव की पहचान अनिल पिता पुष्करलाल पांचाल (25) निवासी ग्राम आक्याकला थाना ताल के रुप में हुई। उक्त टीम द्वारा साक्षीगण के कथन, तकनीकी साक्ष्यों व घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण सोहनसिह पिता गट्टुसिह, भारतसिह पिता गट्टुसिह, चमनसिह पिता भारतसिह जाति राजपुत, अशोक पिता भेरुलाल जाति नाई सभी निवासी माल्या थाना ताल के विरुद्ध पुलिस थाना ताल में अपराध क्रमांक 338/20 धारा 302, 201, 34 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व 26 सितम्बर को आरोपीयो को गिरफ्तार किया गया।

इसलिए उतारा मौत के घाट

आरोपीयों ने पूलिस पूछताछ में बताया कि, मृतक अनिल पांचाल कुछ दिन पूर्व ग्राम माल्या में मिस्त्री का काम करने के लिए गया था, जहां सोहनसिंह पिता गट्टूसिंह के घर पर रहकर ही मिस्त्री का काम करता था, वही पर मृतक की नियत सोहनसिंह की बहन पर खराब हो गई तो, वह उसे परेशान करने लगा जिस पर सोहनसिंह व उसके भाई भारतसिंह का मृतक अनिल पांचाल से विवाद भी हुआ था, जिसके बाद से अनिल नें कई बार सोहनसिंह व उसके भाई भारतसिंह से इसी बात को लेकर विवाद किया, जिससे परेशान होकर 17 सितम्बर को सोहनसिह व उसके भाई भारतसिह नें अपने साथी चमनसिह व अशोक के साथ मिलकर अनिल पांचाल की हत्या करने की योजना बनाकर चमनसिंह के द्वारा उसे फोन करके ग्राम आक्या कला से माल्या जाने वाले कच्चे रास्ते पर सुनसान जगह में बुलाया और चारो नें लाठी-डंडों से पीट-पीटकर अनिल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मृतक के शव को उसकी मोटरसायकल व मोबाईल सहीत ग्राम भरतपुरा व असावता के बीच थाना ताल क्षैत्र मे चंबल नदी के पुल से नदी मे फैक दिया। नदी में अत्यधिक पानी होने से शव बहकर ग्राम बरखेड़ा पहुच गया।

रेल्वे गेट बंद होने से ग्रामीणों को उठानी पड़ रही परेशानी

माही की गूंज, बामनिया। गौरव भंडारी

समीपस्थ ग्राम अमरगढ में विगत करीब 5 वर्षो से अधिक समय से रेल्वे द्वारा रेल्वे क्रासिंग गेट बंद कर दिया गया है। जिससे अमरगढ ग्राम के दूसरी ओर बसे ग्रामों तक सीधा सम्पर्क लगभग बंद सा हो गया है। रेल्वे पटरी के दूसरी ओर बसे लगभग 5 से 7 ग्रामों के ग्रामीणों को अमरगढ की ओर या अंयत्र आने-जाने के लिए कई किलोमीटर घूमकर आवाजाही करना पड रही है। साथ ही मजबूरी में जानजोखिम में डालकर रेल पटरियां भी क्रास करना पड रही है। वैकल्पिक मार्ग में भी परेशानी भरा होने से ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानियां उठानी पड रही है। आम ग्रामीणों की मांग है कि, रेल्वे द्वारा बंद किए गए रेल्वे क्रासिंग गेट को पुनः आरंभ किया जाए या वैकल्पिक मार्ग को आवागमन के अनुरूप बनाया जाए।

हो रही है परेशानी

वैकल्पिक तौर पर रेल पटरियों के नीचे बना हुआ एक नाला है जिसमें असमतल मार्ग बना हुआ है जिसमें से बैलगाडी, टैक्ट्रर आदि बडे वाहनों की निकासी संभव नहीं हो पाती है। पैदल और दो पहिया वाहनों के लिए भी यह मार्ग दुविधा भरा होता है, क्योंकि इस मार्ग में पाईप लाईन से होने वाले पानी की निकासी के कारण अक्सर पानी भरा रहता है। ऐसे में उबड-खाबड और कीचड भरे मार्ग पर बमुशकिल आवाजाही हो पाती है। बारिश के समय तो यह वैकल्पिक मार्ग लगभग बंद ही हो जाता है। स्कूली विघार्थियों को भी विद्यालय के लिए जानजोखिम में डालकर रेल पटरियां क्रास करना पडती है।

ग्रामीण राधेश्याम शर्मा, देवीलाल बसेर, सत्यनारायण सिंगाड, प्रवीण पाटीदार आदि ने बताया कि, रेल्वे स्टेशन के दूसरी छोर बसे ग्रामों में आवाजाही में काफी परेशानी होती है, वाहनों को कई किलोमीटर लम्बा चक्कर लगाकर आवाजाही करना पडती है। रेल्वे क्रासिंग गेट को पुनः आरंभ किया जाना चाहिए जिसका लाभ हजारों ग्रामीणों को मिल सकेगा। तत्कालिक रूप से रेल्वे को नाले वाले मार्ग को दुरूस्तीकरण भी करना चाहिए जिससे पैदल यात्री और छोटे वाहनों को आवागमन में आसानी हो सके। क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा लगातार रेल्वे क्रासिंग गेट को पुनः आरंभ किए जाने हेतु संबंधित विभाग से प्रयास किए है किन्तु रेल्वे आम लोगों की इस बडी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। सरपंच श्रीमती धुलीबाई बिलवाल एवं उपसरपंच नानालाल पाटीदार ने बताया कि, ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर गत वर्ष भी रेल मण्डल प्रबन्धक को आवेदन पत्र दिया गया था किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है एवं ग्रामीणों की परेशानी यथावत बनी हुई है। डीआरएम रतलाम विनीत कुमार गुप्ता का कहना है कि, रेलवे क्रासिंग गेट को पुनः आरंभ किए जाने की मांग से आपने अवगत करवाया है, किन्तु गेट एक बार बंद होने के बाद पुनः चालू किए जाने की प्रक्रिया जटिल है। फिलहाल मैं वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है उसे तत्काल ही करवाता हूं।

खाद्यान्न घोटाले को लेकर आ.जा.से. सहकारी संस्था में एसडीएम का औचक निरीक्षण

गोदाम सील कर दस्तावेज लिए कब्जे में

माही की गूंज, झाकनावदा। आनंन्द सोलंकी

शनिवार शाम झकनावदा में अचानक हलचल तेज हो गई जब पेटलावद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने अचानक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति झकनावद पर पूर्व में हुए खाद्यान्न घोटाले के मामले में दौरा किया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के साथ नायब तहसीलदार की उपस्थिति में सोसाइटी के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के बाद आदिम जाति सेवा सहकारी समिति को सील किया गया, कार्यवाही में एसडीएम के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा।

सर्कस मास्टर पप्पू के प्रकरण को निपटाने की चल रही तैयारी

अचानक हुई कार्यवाही से विकास खण्ड की आदिम जाति सहकारी संस्थाओं की बैचेनी बड़ गई है। खाद्यान्न घोटाले को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती करने में लगा है, मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग खाद्यान्न की कालाबाजारी के सर्कस मास्टर कांग्रेसी पप्पू को इस जाल से निकालने के लिए बड़े स्तर पर सेटिंग कर हेरा-फेरी की तैयारी की जा रही है, जिसकी जानकारी प्रशासन तक पहुँच गई। अधिकारीयो को जांच के दौरान किसी भी प्रकार से संतोषप्रद जबाब नही मिलने पर आनज गोदाम को सील कर रिकॉड जप्त किया गया है।

शिव कस्ट्रक्शन कंपनी का सुपरवाईजर मजदुरों का पैसा लेकर हुआ फरार, पूलिस ने नहीं की रिर्पोट दर्ज

मामलाः दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे में कार्य कर रही षिव कंस्ट्रक्षन कंपनी का

माही की गूंज, खवासा/भामल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे 23, 24 व 25 का प्रमुख ठेकेदार जीआर कंपनी ने पेकेज क्र 24 खवासा चौकी के अंतर्गत रत्नी-भामल के मध्य शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी अहमदाबाद ने पेटी कॉन्ट्रेक्टर के रूप में कन्वर्ट पुलिया का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमे प्रोजेक्ट इंचार्ज के रूप में कार्य करने हेतु गोपाल पिता लक्षन चौहान निवासी खैरा बनुआ, देवरिया उत्तर प्रदेश को नियुक्त कर शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी कार्य कर रही थी की करीब 40 मजदुर प्रोजेक्ट इंचार्ज गोपाल चौहान के अधिन कार्य कर रहे थे, जिनका 1 लाख 2 हजार 360 रूपए व मजदुरों के अन्य खर्च के रूपए के साथ कंपनी का भी रूपया मिलाकर करीब ढाई लाख रूपए शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गोपाल चौहान के बेंक खाते में डाले। उक्त रूपया निजी कार्य से बाहर जा कर वापसी आकर मजदुरो को रूपया देने की बात कह कर गोपाल फरार हो गया और चार-पांच दिनो से अपना मोबाईल भी बन्द कर दिया। मजदुरो का उनकी मजदुरी नही मिलने व उनके खाने-पिने के पैसे भी इंचार्ज गोपाल चौहान लेकर फरार होने के बाद अभी उनके खाने-पिने के भी लाले पड़ गए है, परेशान मजदुर खवासा चौकी में रिर्पोट दर्ज करवाने गए तो चौकी प्रभारी साहब ने बात तो उनकी पुरी सुनी पर चाहे घटना खवासा चौकी क्षैत्र की है पर फरार व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है हम उसे कहा ढूंढेगें का कह कर रिर्पोट लेने से इनकार कर दिया। इस संबध में गूंज ने इंचार्ज से उपर पद पर कार्य कर रहे कर्मचारी अमित पांडे से बात की तो बताया उक्त मामले को कंपनी के मुख्य कार्यालय तक जानकारी दे दी गई है जहां से आश्वासन मिला है कि, मजदुरो का पेमेंट चाहे व्यक्ति फरार हो हो गया है तो भी उनको उनकी मजदुरी दी जाएगी पर पुलिस चौकी में रिर्पोट लेगें तो ही वह रिर्पोट फारर्वड करने पर ही उक्त समस्या का समाधान हो सकता है। हम मजदुरो के साथ पुलिस चौकी खवासा गए थे परंतु साहब ने हमारी बात तो जरूर सूनी पर रिर्पोट नही ली, साहब से एक बार और हम रिर्पोट लेने हेतु निवेदन करेगें।

शिवराज सरकार 15 माह के वनवास के बाद भी प्रसाशन सरकार पर हावी

- सीएम हैल्प लाइन पर की शिकायत पर झुटी जानकारी देकर प्रभारी सीएमओ ने मामले को विलुप्त करने का किया प्रयास

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मील मंसूरी

समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे यह भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मूल मंत्र था, जिनके आदर्शों को अपनाने का दावा तो भाजपा जोर-शोर से करती है, लेकिन उन्हीं की पार्टी द्वारा शासित राज्य मध्यप्रदेश में कहानी कुछ और ही बयां हो रही है।

समस्या के शीघ्र निराकरण हेतु मुख्यमंत्री ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और जिसकी मॉनिटरिंग का कार्य भोपाल स्तर से होता है। शासन की मंशा साफ है कि, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में तथा उपयुक्त निराकरण हो लेकिन भाजपा शासनकाल में नौकरशाही इतनी हावी हो रही है यह मुख्यमंत्री को 15 महीनों के वनवास के बाद भी पता नहीं चला और एक बार फिर जोड़-तोड़ से बनी भाजपा सरकार में नौकरशाही हावी हो रही है और शासन पर प्रशासन भारी पड़ रहा है। वही अधिकारी आज भी बेखोफ होकर अपनी मनमानी चला रहे हैं।

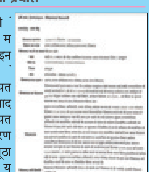

मामला थांदला नगर पंचायत से जुड़ा है जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद कई महीनों तक परीजनों को भटकने के बाद भी यह पता नहीं चल पा रहा है कि उसे कितना पैसा किस मद में मिलना चाहिए था और उसे कितना मिला। मामले की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई और महीनों भटकने के बाद गोलमाल जवाब मिला। प्रभारी सीएमओ के मुताबिक अर्जित अवकाश व अन्य छुट्टियों का लेखा भोपाल में है। जबकि संबंधित थांदला में नौकरी कर रहा था तो सर्विस बुक और छुट्टियों का लेखा भोपाल में क्यों और कैसे है? का सवाल अहम है।

यही नहीं गूंज को मिली जानकारी अनुसार थांदला में ही कार्यरत तीन अन्य कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का नगदीकरण भुगतान किया गया, तो उन्है क्यों नहीं किया गया? यही नहीं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद शिकायत निराकरण का झूठा तथ्य लिखकर शिकायत को विलोपित करने का प्रयास किया जा रहा है। नगरपालिका के तात्कालीन सीएमओ द्वारा यह लिखा जा रहा है कि, नगर पंचायत कार्यालय द्वारा 23 सितंबर 2020 को 1 बजकर 56 मिनट व 1 बजकर 57 मिनट पर दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास संबंधित से किया गया, लेकिन संबंधित से संपर्क नहीं हो पाया। अतः उक्त शिकायत को विलोपित किया जाए जबकि इस समय संबंधित से कोई संपर्क नहीं किया गया और यह प्रकरण अविलोपित है।

इस संबंध में शिकायतकर्ता किशन खोड़े का कहना है कि, मेरे दादा बाबुलाल जी खोड़े व दादी श्रीमती कमलाबाई खोड़े ने अपनी पूरी नौकरी नगर पंचायत थांदला मे की लेकिन अब नगर पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि, सब रिकॉर्ड भोपाल में हैं। इसी दौरान 3 कर्मचारी और सेवानिवृत्त हुए जिनमें लेखा सहायक रहे ज्ञानमल जी जैन की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद परिवार को, जल प्रदाय विभाग में कार्य करने वाले काना भाई चारण व भृत्य रमेश दास बैरागी भी सेवानिवृत्त हुए, इन सभी को अर्जित अवकाश का भुगतान किया गया। साथ ही संबंधित को अनुकंपा नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन मुझे तत्कालिक नगर पंचायत के मुख्य कार्यालन अधिकारी द्वारा लगातार गुमराह किया जाता रहा है। किशन खोड़े ने इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से भी उचित निराकरण करने की मांग की है।

कुंभाखेड़ी पंचायत ने नाली निर्माण के नाम पर किया फर्जीवाड़ा

रोड तो रोड नाली भी खा गई पंचायत, 2017 में स्वीकृत कार्यो में रोज हो रहे नए-नए खुलासे

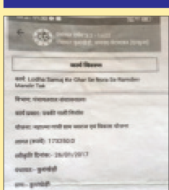

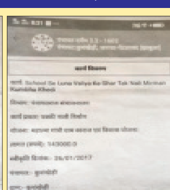

पोर्टल पर दर्ज स्वीकृत कार्य, पर धरातल पर नही बनी नाली

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

सूचना अधिकार में 16 रुपए प्रति पेज राशि वसूल कर सुर्खियो में आई पेटलावद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में नाली निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है, एक बार फिर से वर्ष 2017 में बिना नाली बनाए फर्जी बिल लगा कर राशि आहरण कर ली गई।

रामा निनामा निवासी कुभाखेड़ी द्वारा सूचना अधिकार में मांगी गई जानकारी में पंचायत में ऐसे कई मामले दबा कर जानकारी नही दी गई ताकी पंचायत के भ्रष्टाचार सामने नही आ पाए, लेकिन ऑनलाईन पोर्टल पर मिली जानकारी से फर्जी निर्माण का मामला सामने आया। कुंभाखेडी ग्राम पंचायत में वर्ष 2017 में लोधा समाज के घर से नोरा रामदेव मंदिर तक 1 लाख 73 हजार 250 रुपए की नाली एवं स्कूल से लूणा वालिया के घर तक 1 लाख 43 हजार रुपए का नाली निर्माण महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना से होना था लेकिन ग्राम पंचायत ने दो जगह पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नही किया और पूरी गटर का मल-मुत्र वाला पानी ऐसा पूरा के पूरा पी गए की पूरी की पूरी गटर ही सुखा कर पूरी की पूरी राशि फर्जी बिल लगा-लगाकर आहरण कर ली और महात्मा गांधी के नाम वाली योजना को भी पलीता लगा दिया। ग्राम पंचायत ने अलग-अलग फर्म के फर्जी कमीशन वाले बिल मैड़ा कृषि फार्म बिजोरी, रतराज ट्रेंड्स रायपुरिया के बिल लगा कर राशि आहरण की गई जबकी मौके पर नाली का निर्माण 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नही हुआ हैं।

ग्राम कुभाखेड़ी में नाली निर्माण के स्थान वर्तमान में फैली गंदगी व कीचड़

कीचड़ और गंदगी से परेशान रहवासी

पंचायत ने ग्रामीणों की परेशानी को देखकर नाली निर्माण कर कीचड़ और गंदगी से निजात दिलाने के नाम पर तीन लाख से अधिक का पक्की नाली का निर्माण कार्य स्वीकृत किया लेकिन नाली नहीं बनने से मार्ग पर कीचड़ और गंदगी हो रही है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है, साथ ही बीमारियों का भय भी बना हुआ है। वर्ष 2017 में सीसी रोड निर्माण के साथ-साथ दूसरे निर्माण कार्य में विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है और बिना कार्य किए लाखों की राशि एक-एक पंचायत ने फर्जी बिल लगा-लगाकर निकाल ली गई, जिसकी जाँच के कितने ही मामले सामने आने के बाद भी कार्रवाई नही हो पा रही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422